भारतीय वैश्विक परिषद

समाचार पत्रक

अंक : 30 | जुलाई - सितंबर, 2022

भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ द्वारा कार्यभार संभालने के बाद भारतीय वैश्विक परिषद के महानिदेशक राजदूत विजय ठाकुर सिंह ने 10 सितंबर 2022 को उनसे भेंट की।

भारत-आसियान संबंधों के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय वैश्विक परिषद ने आरआईएस के सहयोग से 20-21 जुलाई, 2022 को 'भू-राजनीतिक बदलाव और अवसर: भारत-दक्षिण पूर्व एशिया संबंधों में नए क्षितिज' विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। मुख्य भाषण भारत सरकार के माननीय विदेश राज्य मंत्री डॉ. राजकुमार रंजन सिंह ने दिया।

भारतीय वैश्विक परिषद ने 8 अगस्त 2022 को डीएआरपीजी के सचिव श्री वी. श्रीनिवास द्वारा 'जी-20 @2023- द रोडमैप टू इंडियन प्रेसीडेंसी' विषय पर एक परिचर्चा का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता भारत सरकार के जी-20 के मुख्य समन्वयक श्री हर्षवर्धन श्रृंगला ने की।

भारतीय वैश्विक परिषद ने 23 अगस्त 2022 को जी-20 के मुख्य समन्वयक और पूर्व विदेश सचिव श्री हर्षवर्धन श्रृंगला की अध्यक्षता में बांग्लादेश के पूर्व विदेश सचिव राजदूत शाहिदुल हक द्वारा "बांग्लादेश विदेश नीति" पर एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया।

"आईओआरए के 25 वर्ष: एक समृद्ध, सतत और शांतिपूर्ण हिंद महासागर क्षेत्र की ओर काम करना" पर 39 वां सप्रू हाउस व्याख्यान 30 सितंबर 2022 को हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के महासचिव महामहिम सलमान अल फारिसी द्वारा दिया गया था।

विषय-सूची

पुस्तक चर्चा- 'क्रंच टाइम: नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस', 13 जुलाई 2022 4

डॉ. तेमजेनमेरेन आओ द्वारा "दक्षिण पूर्व एशिया में उभरते राजनीतिक संवाद: लोकतांत्रिक संक्रमण और क्षेत्रीय स्थिरता" पर सप्रू हाउस पेपर (एसएचपी) चर्चा, 15 जुलाई 2022 4

दक्षिण कोरियाई विद्वान डॉ. वोंडेउक चो, केएनडीए, सियोल, कोरिया गणराज्य, की यात्रा 19 जुलाई 2022 5

भारत-आसियान संबंधों के तीस वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन "भू-राजनीतिक बदलाव और अवसर: भारत-दक्षिण पूर्व एशिया संबंधों में नए क्षितिज", 20-21 जुलाई 2022 5

'भारत-नेपाल विकास साझेदारी: आर्थिक चुनौतियां और अवसर' (बुनियादी संरचना, कनेक्टिविटी, ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा) पर संगोष्ठी, 27 जुलाई 2022 9

श्री. वी. श्रीनिवास, आईएएस द्वारा द रोड मैप टू इंडियन प्रेसिडेंसी"" विषय पर व्याख्यान, 8 अगस्त 2022 10

डॉ. अंकिता दत्ता, अध्येता द्वारा लिखित, भारतीय वैश्विक परिषद सप्रू हाउस पेपर "क्यों विसेग्राद 4? - भारत-वी4 सहयोग की संभावनाएं पर चर्चा, 22 अगस्त 2022 12

राजदूत शाहिदुल हक, पूर्व विदेश सचिव, बांग्लादेश द्वारा "बांग्लादेश विदेश नीति" पर विशेष व्याख्यान, 23 अगस्त 2022 12

"एशिया में अमेरिकी विस्तारित परमाणु निवारण" पर गोलमेज चर्चा, 25 अगस्त 2022 14

"पाकिस्तान के निरंतर राजनीतिक और आर्थिक संकट" पर पैनल चर्चा, 30 अगस्त 2022 14

यू मिन जिन, संस्थापक सदस्य और कार्यकारी निदेशक, इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजी एंड पॉलिसी, म्यांमार द्वारा "म्यांमार में स्थिति" पर वार्ता, 5 सितंबर 2022 16

"हिंद महासागर में भारत और द्वीप राज्य: भू-राजनीति और सुरक्षा परिप्रेक्ष्य विकसित करना" पर भारतीय वैश्विक परिषद वेब आधारित सम्मेलन, 6 सितंबर 2022 16

आईसीसीआर के जेन-नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क प्रोग्राम के विदेशी प्रतिनिधियों के 5वें बैच के साथ चर्चा, 7 सितंबर 2022.... 18

भारत-पेरू संबंधों पर भारतीय वैश्विक परिषद्-पीयूसीपी, लीमा संवाद: क्षेत्र और द्विपक्षीय संबंधों के साथ जुड़ाव, 8 सितंबर 2022 19

भारतीय वैश्विक परिषद के अध्येता डॉ. श्रीपति नारायणन द्वारा लिखित "क्रा के इस्तमुस: मलय प्रायद्वीप को रेल और नहर द्वारा जोड़ना" पर सप्रू हाउस पेपर (एसएचपी) चर्चा, 13 सितंबर 2022 21

हिंद महासागर रिम अकादमिक समूह (आईओआरएजी) की 27 वीं बैठक, 14 सितंबर 2022 21

डॉ. लक्ष्मी प्रिया, अध्येता, भारतीय वैश्विक परिषद, द्वारा लिखित "छोटे खाड़ी राष्ट्रों की बदलती विदेश नीति: संयुक्त अरब अमीरात का एक केस स्टडी" पर सप्रू हाउस पेपर (एसएचपी) चर्चा, 15 सितंबर 2022 22

"दक्षिण चीन सागर में रणनीतिक प्रतिस्पर्धा: हित, रक्षा और कूटनीति" पर भारतीय वैश्विक परिषद- इंडिया फ्यूचर फाउंडेशन संगोष्ठी, 16 सितंबर 2022 22

डॉ. संकल्प गुर्जर, अध्येता, भारतीय वैश्विक परिषद द्वारा "उत्तर पश्चिम हिंद महासागर की भू-राजनीति: पश्चिम एशियाई राष्ट्रों की रणनीतिक उपस्थिति की खोज" पर लिखित सप्रू हाउस पेपर (एसएचपी) चर्चा, 23 सितंबर 2022 23

भारतीय वैश्विक परिषद के अध्येता डॉ. टेशू सिंह द्वारा "चीन और हिंद-प्रशांत: मुद्दे और चिंताएं" पर लिखित सप्रू हाउस पेपर (एसएचपी) चर्चा, 29 सितंबर 2022 24

डॉ. अरशद, अध्येता, भारतीय वैश्विक परिषद, द्वारा "तुर्की-मिस्र संबंधों के दस वर्ष: टकराव से सुलह" पर लिखित सप्रू हाउस पेपर (एसएचपी) चर्चा, 29 सितंबर 2022 24

हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (आईओआरए) के महासचिव महामहिम सलमान अल फरीसी द्वारा "आईओआरए के 25 वर्ष: एक समृद्ध, सतत और शांतिपूर्ण हिंद महासागर क्षेत्र की दिशा में काम करना" पर 39 वां सप्रू हाउस व्याख्यान, 30 सितंबर 2022 25

आउटरीच कार्यक्रम 26

प्रकाशन 28

इंडिया क्वार्टरली - संपादकीय 31

पुस्तक चर्चा- 'क्रंच टाइम: नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस', 13 जुलाई 2022

भारतीय वैश्विक परिषद ने 13 जुलाई 2022 को सप्रू हाउस में डॉ. श्रीराम चौलिया द्वारा लिखित पुस्तक 'क्रंच टाइम: नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस' पर एक चर्चा का आयोजन किया। चर्चा की अध्यक्षता कजाकिस्तान, स्वीडन और लातविया में भारत के पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार ने की और चर्चा करने वालों में रणनीतिक और विदेश नीति विश्लेषक डॉ. हरिंदर सेखों और पीवीएसएम, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम (सेवानिवृत्त) लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. सिंह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर, दक्षिणी कमान के पूर्व जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ शामिल थे।

पैनलिस्टों ने कहा कि पुस्तक भारत के सामने आने वाली सुरक्षा चुनौतियों का अवलोकन करती है और कैसे भारत ने अनिश्चित भू-राजनीतिक वातावरण, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खतरों और एक अशांत पड़ोस के प्रति सचेत रहते हुए हाल के वर्षों में अपनी सुरक्षा नीतियों में एक व्यापक और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है। पुस्तक प्रधानमंत्री मोदी के सक्षम नेतृत्व को निहारती है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों के लिए रचनात्मक और लीक से हटकर प्रतिक्रियाएं लेकर आए हैं और उरी सर्जिकल स्ट्राइक, डोकलाम संकट, बालाकोट हवाई हमलों के कुशलता से निपटने का लेखा-जोखा प्रदान करते हैं। यह देखा गया कि दुनिया में भारत एक ऐसे राष्ट्र के रूप में उदय हो रहा है जो अपने हितों और पदों को स्पष्ट करने से डरता नहीं है।

डॉ. तेमजेनमेरेन आओ द्वारा "दक्षिण पूर्व एशिया में उभरते राजनीतिक संवाद: लोकतांत्रिक संक्रमण और क्षेत्रीय स्थिरता" पर सप्रू हाउस पेपर (एसएचपी) संवाद, 15 जुलाई 2022

भारतीय वैश्विक परिषद ने 15 जुलाई 2022 को भारतीय वैश्विक परिषद के अध्येता डॉ. तेमजेनमेरेन आओ द्वारा 'दक्षिण पूर्व एशिया में उभरते राजनीतिक संवाद: लोकतांत्रिक संक्रमण और क्षेत्रीय स्थिरता' पर एक सप्रू हाउस पेपर चर्चा का आयोजन किया। चर्चा की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के पूर्व प्रोफेसर जीवीसी नायडू और सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली के वरिष्ठ रिसर्च एसोसिएट अंगशुमन चौधरी और इंडिया फाउंडेशन, नई दिल्ली की वरिष्ठ अध्येता डॉ. सृष्टि पुखरेम ने की। यह पेपर दक्षिण पूर्व एशिया में उभरते राजनीतिक संवाद को चिह्नित करता है और उन कारकों की पड़ताल करता है जो सामाजिक और आर्थिक कारकों, जातीय-धार्मिक लाइनों पर आधारित विद्रोह, राजनीतिक विवादों और सेना की भूमिका सहित लोकतांत्रिक संक्रमण और क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं।

दक्षिण कोरियाई विद्वान डॉ. वोंडेउक चो, केएनडीए, सियोल, कोरिया गणराज्य (आरओके) का दौरा, 19 जुलाई, 2022

कोरियाई राष्ट्रीय राजनयिक अकादमी (केएनडीए), सियोल के सदस्य अनुसंधान प्रोफेसर डॉ. वोंडेउक चो ने 19 अगस्त 2022 को भारतीय वैश्विक परिषद का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान, उन्होंने परिषद के अनुसंधान संकाय के साथ चर्चा की। चर्चा का विषय हिंद-प्रशांत क्षेत्र के संबंध में दक्षिण कोरिया की विदेश नीति थी। चर्चा के दौरान, यह नोट किया गया कि दक्षिण कोरिया में, वर्तमान यूं सुक येओल की सरकार अन्य हिंद-प्रशांत देशों के साथ संबंधों को बढ़ावा देने के लिए उत्सुक है। क्वाड देश दक्षिण कोरिया के लिए महत्वपूर्ण साझेदार हैं। कोरिया गणराज्य नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का समर्थन करता है। कोरियाई प्रायद्वीप के आसपास का रणनीतिक माहौल जटिल बना हुआ है। दक्षिण कोरिया अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्धा पर पैनी नजर रखे हुए है। रणनीतिक रूप से, हिंद-प्रशांत के संदर्भ में, भारत एक महत्वपूर्ण प्रमुख शक्ति है, एजेंडा सेटिंग में एक अग्रणी नायक और हिंद-प्रशांत में एक निवासी शक्ति है। द्विपक्षीय रूप से, भारत और दक्षिण कोरिया के लिए सहयोग के संभावित क्षेत्र आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन, डिजिटल मुद्रा और रक्षा उद्योग सहयोग, विशेष रूप से पनडुब्बी और नौसेना जहाज निर्माण में, और समुद्री डोमेन जागरूकता सहित समुद्री सहयोग हो सकते हैं।

भारत-आसियान संबंधों के तीस वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में "भू-राजनीतिक परिवर्तन और अवसर: भारत-दक्षिण पूर्व एशिया संबंधों में नए क्षितिज" पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 20-21 जुलाई 2022

विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली (आरआईएस) में आसियान इंडिया सेंटर (एआईसी) के सहयोग से भारतीय वैश्विक परिषद ने 20-21 जुलाई 2022 को "भू-राजनीतिक बदलाव और अवसर: भारत-दक्षिण पूर्व एशिया संबंधों में नए क्षितिज" विषय पर भारत-आसियान संबंधों के तीस वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। संगोष्ठी में थिंक टैंक, शैक्षणिक संस्थानों के चालीस से अधिक वक्ताओं के साथ-साथ भारत और आसियान देशों के पूर्व राजनयिक भी शामिल थे।

अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन सत्र 20 जुलाई 2022 को सप्रू हाउस में व्यक्तिगत रूप से आयोजित किया गया था। भारतीय वैश्विक परिषद् के महानिदेशक राजदूत विजय ठाकुर सिंह और भारत में सिंगापुर गणराज्य के उच्चायुक्त महामहिम श्री साइमन वोंग वी कुएन ने टिप्पणी की। एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली के वरिष्ठ अध्येता डॉ. सी राजा मोहन ने विशेष टिप्पणियां कीं। मुख्य भाषण भारत सरकार के

माननीय विदेश राज्य मंत्री डॉ. राजकुमार रंजन सिंह ने दिया।

राज्य मंत्री डॉ. राजकुमार रंजन सिंह ने कहा कि आसियान-भारत संबंध भारत की विदेश नीति के प्रमुख स्तंभों में से एक है जिसने भारत के व्यापक हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में मदद की है। दक्षिण पूर्व एशिया वास्तव में 21 वीं सदी की दुनिया के गुरुत्वाकर्षण के आर्थिक और भू-राजनीतिक केंद्र के रूप में उभरा है। आसियान एकता और केंद्रीयता इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। भू-राजनीतिक बदलावों ने क्षेत्र की सुरक्षा और विकास सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय सहयोग को सुदृढ़ करने के महत्व को रेखांकित किया है। भारत और आसियान को केंद्रित व्यावहारिक सहयोग के साथ अपने सहयोग को नए क्षितिज पर विस्तारित करने की आवश्यकता है। भारत-आसियान सहयोग क्षेत्र में स्थिरता का एक कारक है।

भारत में सिंगापुर गणराज्य के उच्चायुक्त महामहिम श्री साइमन वोंग वी कुएन ने कहा कि हाल ही में भारत-आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के लिए अधिक रणनीतिक रूप से जुड़ने का मार्ग प्रशस्त किया है। स्टैगफ्लेशन, वैश्विक व्यापार का समतल होना, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, मांग में व्यवधान, युवा बेरोजगारी, अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्धा, यूक्रेन में लंबे समय तक युद्ध भारत और आसियान के सामने अंतर-लॉकिंग चुनौतियों में से हैं। भारत और आसियान डिजिटल भुगतान कनेक्ट, स्टार्ट-अप और फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र के लिंक-अप, कौशल केंद्रों और विश्वविद्यालय विकास में सहयोग और हरित ऊर्जा, स्वास्थ्य और फार्मा क्षेत्रों में सहयोग के माध्यम से अपनी साझेदारी को सुदृढ़ कर सकते हैं।

एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ अध्येता डॉ. सी राजा मोहन ने कहा कि हिंद-प्रशांत निर्माण आसियान को इस क्षेत्र के केंद्र में रखता है और इसलिए, आसियान की केंद्रीयता अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। क्वाड यहां आसियान की जगह लेने के लिए नहीं बल्कि मिलकर काम करने के लिए आया है। भारत और आसियान को इस विचार पर अपनी निर्भरता को दूर करने के लिए अधिक सुरक्षा सहयोग विकसित करने की आवश्यकता है कि क्षेत्र की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका और चीन की आवश्यकता है। भारत और आसियान को रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर सामूहिक और द्विपक्षीय रूप से मिलकर काम करना होगा। वर्तमान भू-राजनीतिक किण्वन और अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्धा का प्रत्युत्तर भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के बीच अधिक सहयोग है, कम नहीं।

सम्मेलन के तकनीकी सत्र वर्चुअल मोड में आयोजित किए गए थे। "क्षेत्रीय और वैश्विक रुझान" पर पहले सत्र की अध्यक्षता गेटवे हाउस, मुंबई के प्रतिष्ठित अध्येता और भारतीय वैश्विक परिषद्, नई दिल्ली के पूर्व महानिदेशक राजदूत राजीव भाटिया ने की। सत्र में वक्ता डॉ. कुइक चेंग-चवी, प्रमुख और एसोसिएट प्रोफेसर, सेंटर फॉर एशियन स्टडीज, इंस्टीट्यूट ऑफ मलेशियन एंड इंटरनेशनल स्टडीज (आईकेएमएएस),

नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया (यूकेएम), बंगी; डॉ. राहुल मिश्रा, निदेशक, आसियान क्षेत्रवाद केंद्र, यूनिवर्सिटी मलाया (सीएआरयूएम), कुआलालंपुर; शंकरी सुंदररमन, सेंटर फॉर इंडो-पैसिफिक स्टडीज, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू), नई दिल्ली; दीपक, चीनी और चीन अध्ययन के प्रोफेसर, चीनी और दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू), नई दिल्ली। सत्र में कोविड-19 महामारी, अमेरिका-चीन टकराव, हिंद-प्रशांत और यूक्रेन संकट सहित वर्तमान भू-राजनीतिक परिदृश्य को परिभाषित करने वाले प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय रुझानों पर चर्चा की गई। यह देखा गया कि हिंद-प्रशांत क्वाड की तुलना में एक व्यापक निर्माण है जिसमें आर्थिक और गैर-पारंपरिक सुरक्षा शामिल है। क्वाड आसियान के विरुद्ध नहीं है और मौजूदा भू-राजनीतिक रुझान भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच सुदृढ़ संबंधों का मामला बनाते हैं।

"अतीत और वर्तमान के बीच: दक्षिण पूर्व एशिया में भारत के पदचिह्नों का पता लगाना" विषय पर दूसरे सत्र की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू), नई दिल्ली के पूर्व प्रोफेसर प्रोफेसर बालादास घोषाल ने की। सत्र में वक्ताओं में प्रोफेसर जोफे संतारिता, एशियाई अध्ययन के प्रोफेसर, एशियाई केंद्र, फिलीपींस विश्वविद्यालय दिलिमन और फिलीपींस, मनीला के आसियान अध्ययन संघ के अध्यक्ष; डॉ. नलिना गोपाल, सामाजिक इतिहासकार और विरासत क्यूरेटर, सिंगापुर; सुचन्द्र घोष, हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद; राजीव रंजन चतुर्वेदी, एसोसिएट प्रोफेसर, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा थे। सत्र में भारत और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने वाले सभ्यता पहलुओं और समकालीन वास्तविकताओं के लिए इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा की गई। इस सत्र में भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों के बारे में विस्तार से बताया गया। यह देखा गया कि दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय प्रभावों के अध्ययन और भारत पर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की संस्कृतियों के प्रभाव पर समान जोर देने की आवश्यकता है। पर्यटन को बढ़ावा देने में नए जोश, दक्षिण पूर्व एशिया में विरासत स्थलों के जीर्णोद्धार में भारतीय विकास सहायता और संग्रहालयों के बीच सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया गया। सत्र में कहा गया कि भारत और दक्षिण पूर्व एशिया दोनों की बहुलतावादी प्रकृति ने उनके मैत्रीपूर्ण और घनिष्ठ संबंधों के लिए दृढ़ आधार प्रदान किया।

"क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से आम सहमति बनाना" पर तीसरे सत्र की अध्यक्षता बैंकॉक के चुलालोंगकोर्न विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एमेरिटस प्रोफेसर सुथीफांड चिराथिवेट ने की। सत्र में वक्ता डॉ. रविचंद्रन मूर्ति, एसोसिएट प्रोफेसर, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सामरिक अध्ययन, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया (यूकेएम), कुआलालंपुर; श्री संजय पुलिपाका, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और सुरक्षा पर स्वतंत्र शोधकर्ता, हैदराबाद; और डॉ. टेमजेनमेरेन एओ, अध्येता, भारतीय वैश्विक परिषद्, नई दिल्ली थे। सत्र में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच तालमेल बनाने की दिशा में दृष्टिकोण पर चर्चा की गई। आसियान देशों के बीच हिंद-प्रशांत क्षेत्र के आकर्षण को बढ़ाने के साथ, आईपीओआई और एओआईपी के बीच अभिसरण पर निर्माण करने और आईपीईएफ के बढ़े हुए आर्थिक जुड़ाव के तहत सूचीबद्ध चार मुख्य स्तंभों के बीच सहयोग करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। यह नोट किया गया कि भारत और दक्षिण पूर्व एशिया

आईपीईएफ के तहत लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण कर सकते हैं।

"बदलती सुरक्षा गतिशीलता" पर चौथे सत्र की अध्यक्षता राजदूत अनिल वाधवा, पूर्व सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने की। वक्ताओं में वियतनाम एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज (वीएएसएस), हनोई के इंस्टीट्यूट फॉर साउथईस्ट एशियन स्टडीज (आईएसईएएस) के उप निदेशक डॉ. वो जुआन विन्ह; डॉ. जिरयुध सिंथुफान, सहायक प्रोफेसर, चुलालोंगकोर्न विश्वविद्यालय, बैंकॉक, डॉ. एम. मयिलवागनन, एसोसिएट प्रोफेसर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज (एनआईएएस), बेंगलुरु; और डॉ. उदय भानु सिंह, पूर्व वरिष्ठ रिसर्च एसोसिएट, मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस (एमपी-आईडीएसए), नई दिल्ली थे। सत्र में कहा गया कि अमेरिका और चीन के बीच हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण सामान्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया और विशेष रूप से आसियान को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। आसियान क्षेत्र में शांति के लिए एक उत्प्रेरक है; मौजूदा तनाव और चुनौतियों के लिए एक बहुपक्षीय तंत्र की

आवश्यकता है जो आसियान द्वारा रचनात्मक वार्ता के लिए सभी प्रमुख हितधारकों को एक साझा मंच पर लाकर प्रदान किया जाता है। आसियान को प्रमुख सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी भूमिका बढ़ाने की आवश्यकता है।

आर्थिक सहयोग पर पांचवें सत्र की अध्यक्षता राजदूत गुरजीत सिंह, प्रोफेसर, आईआईटी इंदौर और इंडोनेशिया और आसियान में भारत के पूर्व राजदूत ने की। वक्ताओं में सिंगापुर के इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज (आईएसएएस) के विजिटिंग अध्येता डॉ. मोहम्मद मसूदुर रहमान; डॉ. वॉचरस लीलावत, सलाहकार (मानद), बोलिगर एंड कंपनी, बैंकॉक और पूर्व कार्यकारी निदेशक, मेकांग इंस्टीट्यूट (एमआई); और प्रोफेसर बिस्वजीत नाग, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी), नई दिल्ली थे। सत्र में महामारी के बाद की दुनिया में भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच आर्थिक सहयोग से संबंधित मुद्दों और अवसरों पर चर्चा की गई। भौतिक और डिजिटल दोनों कनेक्टिविटी बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया, जो व्यापार, वाणिज्य और लोगों से लोगों के संबंधों को बढ़ावा देने में मदद करेगा। परिवहन कनेक्टिविटी के लिए बिम्सटेक मास्टर प्लान और स्थानीय क्षमता निर्माण में मेकांग गंगा सहयोग की अपार संभावनाओं का उल्लेख किया गया। कपड़ा क्षेत्र की पहचान इस क्षेत्र में वैश्विक मूल्य श्रृंखला विकसित करने की क्षमता के लिए की गई थी। यह भी बताया गया कि त्रिपक्षीय राजमार्ग जैसी बुनियादी संरचना परियोजनाओं को पूरी तरह से फायदेमंद होने के लिए भारतीय पक्षों पर औद्योगिक क्षेत्रों के विकास की आवश्यकता होगी।

"विकास साझेदारी" पर छठे सत्र की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू), नई दिल्ली के एमेरिटस प्रोफेसर प्रोफेसर एस.डी. मुनि ने की। वक्ताओं में आसियान अध्ययन केंद्र, आईएसईएएस - यूसुफ इशाक इंस्टीट्यूट, सिंगापुर के प्रमुख शोधकर्ता (अर्थशास्त्र) डॉ. सिथानोंक्से सुवनाफाक्डी; डॉ. सोमदेथ बोधिसाने, उद्योग और वाणिज्य संस्थान (आईआईसी), उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय (एमओआईसी), वियनतियाने; डॉ. उमा पुरुषोत्तम, सहायक प्रोफेसर, अंतर्राष्ट्रीय संबंध

विभाग, केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय, केरल; और डॉ. संपा कुंडू, सलाहकार, आसियान-भारत केंद्र (एआईसी), आरआईएस, नई दिल्ली थे। सत्र में दक्षिण पूर्व एशिया में भारत की विकास साझेदारी के पहलुओं पर चर्चा की गई जिसमें लाइन ऑफ क्रेडिट, छात्रवृत्ति और विरासत स्थल बहाली शामिल हैं। भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया में अंग्रेजी भाषा प्रशिक्षण केंद्र, आईटी केंद्र, महिला प्रशिक्षण केंद्र आदि बनाए हैं। भारत मेकांग देशों में त्वरित प्रभाव परियोजनाओं का वित्तपोषण कर रहा है और सीएलएमवी देशों में भौतिक और डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय, आईसीसीआर, आईटीईसी और आईआईटी के माध्यम से आसियान के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जा रही है। विकास सहयोग भारत-आसियान संबंधों का मुख्य आधार रहा है।

"चार्टिंग द न्यू एजेंडा: पाथवेज टू बियॉन्ड एक्ट ईस्ट" पर सातवें सत्र की अध्यक्षता राजदूत पो सोथिराक, कार्यकारी निदेशक, कंबोडियाई इंस्टीट्यूट फॉर कोऑपरेशन एंड पीस (सीआईसीपी), नोम पेन्ह ने की। वक्ताओं में ब्रैडली मुर्ग, विशिष्ट वरिष्ठ अध्येता, कंबोडियाई इंस्टीट्यूट फॉर कोऑपरेशन एंड पीस (सीआईसीपी), नोम पेन्ह; सिनेनात सेर्मचीप, सहायक प्रोफेसर, चुलालोंगकोर्न विश्वविद्यालय, बैंकॉक; प्रोफेसर अमिता बत्रा, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू), नई दिल्ली; और डॉ. प्रबीर डे, प्रोफेसर, आसियान-भारत केंद्र (एआईसी), आरआईएस, नई दिल्ली और डॉ. तुहिंसुभ्रा गिरी, अध्येता, आरआईएस, नई दिल्ली थे। सत्र में द्विपक्षीय और क्षेत्रीय स्तर पर भारत और आसियान देशों के बीच सहयोग के नए एजेंडे पर चर्चा की गई। वर्तमान भू-राजनीतिक और भू-आर्थिक माहौल के प्रकाश में, सत्र ने समुद्री, आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण, डिजिटल कनेक्टिविटी, आर्थिक एकीकरण और वैश्विक कॉमन्स की भलाई में संबंधों को और गहरा करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, जो वास्तव में संबंधों को बढ़ाने में मदद करेगा।

'भारत-नेपाल विकास साझेदारी: आर्थिक चुनौतियां और अवसर' (बुनियादी संरचना, कनेक्टिविटी, ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा) पर संगोष्ठी, 27 जुलाई 2022

भारतीय वैश्विक परिषद ने 27 जुलाई, 2022 को "भारत-नेपाल विकास साझेदारी: आर्थिक चुनौतियां और अवसर - बुनियादी संरचना, कनेक्टिविटी, ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा" पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में दो सत्र हुए, जिसमें दोनों की अध्यक्षता नेपाल में भारत के पूर्व राजदूत राजदूत रंजीत राय ने की। भारतीय वैश्विक परिषद की महानिदेशक राजदूत विजय ठाकुर सिंह और भारत में नेपाल के राजदूत डॉ. शंकर प्रसाद शर्मा ने उद्घाटन सत्र में अपने उद्घाटन भाषण दिए। "बुनियादी संरचना, कनेक्टिविटी और ऊर्जा में विकास साझेदारी को बढ़ावा देना - स्थिति का आकलन और भावी राह" विषय पर पहले सत्र में पैनलिस्ट थे: श्री सुनील केसी, सीईओ, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिप्लोमेसी एंड इंटरनेशनल अफेयर्स (एआईडीआईए), काठमांडू; राजदूत विजय कांत कर्ण, डेनमार्क में नेपाल के पूर्व राजदूत, कार्यकारी अध्यक्ष, सेंटर फॉर सोशल इनक्लूजन एंड फेडरलिज्म, काठमांडू; प्रोफेसर महेंद्र पी लामा, सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली; और डॉ. निहार नायक, अध्येता, मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, नई दिल्ली।

"शिक्षा और स्वास्थ्य में विकास साझेदारी को बढ़ावा देना - स्थिति का आकलन और भावी राह" पर सत्र II के पैनलिस्टों में शामिल थे: डॉ. उद्धव प्याकुरेल, एसोसिएट प्रोफेसर, ग्लोबल एंगेजमेंट डिवीजन, स्कूल ऑफ आर्ट्स, काठमांडू विश्वविद्यालय के प्रवक्ता / कमल देव भट्टराई, सहायक संपादक, अन्नपूर्णा एक्सप्रेस; और श्री गौतम घोष, वरिष्ठ निदेशक, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।

उद्घाटन सत्र में इस बात को रेखांकित किया गया कि भारत की पड़ोसी प्रथम नीति नेपाल के साथ संबंधों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। नेपाल भारत की विकास सहायता प्राप्त करने वाले सबसे बड़े प्राप्तकर्ताओं में से एक रहा है। आज, संबंध व्यापक आधार पर हैं और इसके दायरे में उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, दूरसंचार, सड़क और रेल कनेक्टिविटी और ऊर्जा शामिल हैं। इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि इस मोड़ पर उपर्युक्त विषय पर संगोष्ठी के आयोजन से अवसरों का दोहन करने और विशेष रूप से आर्थिक क्षेत्र में बाधाओं को दूर करने में मदद मिल सकती है। पांच व्यापक क्षेत्र जिनमें विशाल अवसर हैं, उनमें शामिल हैं: i) व्यापार; ii) ऊर्जा: भारत को ऊर्जा का निर्यात भारी व्यापार घाटे की भरपाई कर सकता है; पर्यटन: पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को और विकसित कर रहा है; iv) आईटी: नेपाल ई-कॉमर्स सहित आईटी क्षेत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है; 5) स्वास्थ्य एवं शिक्षा: तृतीयक स्वास्थ्य और शिक्षा को भारतीय कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यमों के साथ सुदृढ़ किया जा सकता है।

चर्चाओं में रेखांकित किया गया कि यह संगोष्ठी कोविड-19 और यूक्रेन संकट के कारण काफी वैश्विक प्रवाह के समय हो रही है, जिसका तेल की कीमतों, खाद्य सुरक्षा पर भारी प्रभाव पड़ा है और दक्षिण एशिया सहित कई देशों में कठिनाइयां पैदा हुई हैं। अधिकांश देश उच्च मुद्रास्फीति से जूझ रहे हैं और राजकोषीय नीतियों को कड़ा कर रहे हैं। भारत की पड़ोस प्रथम नीति से वैश्विक संकट की चुनौतियों से बेहतर तरीके से निपटने में मदद मिलेगी। पड़ोस प्रथम नीति का उद्देश्य एक परस्पर, अन्योन्याश्रित खुली आर्थिक परिवेश बनाना है जहां इस क्षेत्र का प्रत्येक सदस्य अधिकतम अपने तुलनात्मक लाभ का लाभ उठा सकता है। भारत-नेपाल कनेक्टिविटी संबंधों को प्रगाढ़ करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। निजी निवेश के साथ भारत (द्वितीय सृजन) और नेपाल (प्रथम सृजन) में बिजली क्षेत्र के सुधारों के कारण पिछले कुछ वर्षों में द्विपक्षीय रूप से ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। पूरी हो चुकी परियोजनाओं का समय पर पूरा होना, निगरानी करना और रखरखाव महत्वपूर्ण है। यह भी सुझाव दिया गया कि भारत को बुनियादी संरचना और पनबिजली क्षेत्रों में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। पारेषण क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां भारत नेपाल की सहायता कर सकता है। यह देखा गया कि हाल के वर्षों में लोगों के बीच संपर्क में धीमी गति आई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग भारत और नेपाल के बीच सहयोग के केंद्रीय क्षेत्रों में से एक है और इस पर विस्तार से चर्चा की गई।

श्री. वी. श्रीनिवास, आईएएस द्वारा "जी-20@2023- द रोड मैप टू इंडियन प्रेसिडेंसी" विषय पर व्याख्यान, 8 अगस्त 2022

भारतीय वैश्विक परिषद ने 8 अगस्त 2022 को 'जी 20 @ 2023 - द रोडमैप टू इंडियन प्रेसीडेंसी' शीर्षक से एक वार्ता का आयोजन किया। भारतीय वैश्विक परिषद की महानिदेशक राजदूत विजय ठाकुर सिंह ने उद्घाटन भाषण दिया। चर्चा की अध्यक्षता जी-20 के मुख्य

समन्वयक और भारत के पूर्व विदेश सचिव श्री हर्षवर्धन श्रृंगला ने की और इसके बाद भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने चर्चा की। विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (आरआईएस) के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी पैनलिस्ट थे। इस कार्यक्रम में कई मिशनों के प्रमुखों, इंडोनेशिया और इटली के दूतावासों के अधिकारियों ने भाग लिया, जो भारत के साथ जी 20 तिकड़ी के सदस्य हैं, और रणनीतिक और अकादमिक समुदाय के सदस्य हैं। राजदूत विजय ठाकुर सिंह ने उद्घाटन भाषण देते हुए इस बात पर प्रकाश डाला कि जी 20 शिखर सम्मेलन बहुपक्षीय कूटनीति के भारत के कैलेंडर में एक प्रमुख कार्यक्रम होगा। भारत के पास जी-20 को देने के लिए बहुत कुछ है। यह एक बड़े उपभोक्ता आधार के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। यह फार्मा और आईटी क्षेत्र में अग्रणी है। भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न आधार है और यह डिजिटल भुगतान में वैश्विक नायक है। जुलाई 2021 में, यूएस $ 6.28 बिलियन लेनदेन के साथ, भारत ने दुनिया में डिजिटल लेनदेन की सबसे अधिक मात्रा बनाई। जी-20 में भारत की भूमिका इस अहसास से उपजी है कि एक प्रमुख विकासशील देश होने के नाते, भारत की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय प्रणाली में हिस्सेदारी है।जी-20 के संस्थापक सदस्य के रूप में, भारत विकासशील देशों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण हितों के मुद्दों को उठाने के लिए इस मंच का उपयोग करना जारी रखता है। अपनी अध्यक्षता में, भारत समूह के अन्य सदस्यों के साथ काम करने और सार्थक परिणाम लाने की कोशिश करेगा।

श्री हर्षवर्धन श्रृंगला ने स्पष्ट किया कि यह भारत के लिए अपनी उपलब्धियों को प्रदर्शित करने का एक शानदार अवसर है। जी-20 के सदस्य मिलकर दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 80 प्रतिशत से अधिक, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के 75 प्रतिशत और विश्व की दो तिहाई आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी 5 स्थायी सदस्य और जी-7 और ब्रिक्स के सभी सदस्य शामिल हैं। भारत समूह के अध्यक्ष के रूप में एक बड़ी जिम्मेदारी संभालेगा। यद्यपि जी-20 की शुरुआत मुख्य रूप से एक वित्तीय और आर्थिक समूह के रूप में हुई थी, लेकिन आज यह वैश्विक विकास के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य संकट, खाद्य सुरक्षा आदि की एक व्यापक सूची को कवर करता है। भारत न केवल विभिन्न देशों के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों जैसे सभी हितधारकों के साथ जुड़ता है, बल्कि विभिन्न थिंक टैंक और कई गैर-सरकारी समूहों के साथ भी जुड़ता है जो जी 20 लक्ष्यों में योगदान दे सकते हैं। जी-20 के अध्यक्ष के रूप में, भारत प्रमुख और फोकस क्षेत्रों की पहचान करके, चर्चा आयोजित करके और परिणाम प्रदान करके एजेंडा निर्धारित करेगा। भारत महत्वपूर्ण महत्व के प्राथमिकता वाले मुद्दों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन को भी रेखांकित और सुदृढ़ करेगा। भारत जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर अथक प्रयास कर रहा है और प्रतिबद्ध समयसीमा से नौ वर्ष पहले गैर-जीवाश्म ईंधन की 40 प्रतिशत ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य हासिल कर लिया है। पेट्रोल से इथेनॉल मिश्रण का 10 प्रतिशत लक्ष्य प्रतिबद्ध समय से 5 महीने पहले हासिल कर लिया जाएगा।

श्री श्रीनिवास ने कहा कि भारत बहुपक्षवाद और लोकतंत्र के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और जी-20 की अध्यक्षता भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण होगा। आजादी के बाद से, भारत बहुपक्षीय संस्थानों के साथ जुड़ा हुआ है। यह ब्रेटन वुड्स सिस्टम और संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य रहा है। बहुपक्षवाद पर जोर देने के साथ शासन का भारत का समावेशी मॉडल जी 20 नेतृत्व के बेहतरीन वर्षों में से एक का वादा करता है, जिसमें बहुपक्षवाद फल-फूल सकता है और जी 20 अंतर्राष्ट्रीय वार्ता की प्रक्रियाओं को बदलते हुए वैश्वीकरण को सुरक्षित, टिकाऊ बनाने में गंभीर योगदान दे सकता है। वर्ष 2021 में इतालवी अध्यक्षता ने लोगों, ग्रह और समृद्धि पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि 2022 में इंडोनेशियाई अध्यक्षता ने एक साथ ठीक होने, सुदृढ़ होने पर प्रकाश डाला। भारत की अध्यक्षता जी-20 में भारत के योगदान और बहुपक्षवाद को कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है, इस पर प्रकाश डालेगी। भारतीय अध्यक्षता के लिए रोडमैप को अंतिम रूप देने से पहले यह देखना महत्वपूर्ण है कि अन्य सदस्यों द्वारा आयोजित पूर्व की अध्यक्षता में क्या हुआ था। एजेंडा रियाद, रोम और जकार्ता शिखर सम्मेलनों की विज्ञप्ति से लिया जा सकता है। जी-20 अध्यक्षता भारत के लोकतंत्र के लिए मील का पत्थर होगा। यह व्यापक रूप से महसूस किया जाता

है, ऐसे समय में जब बहुपक्षवाद का संकट होता है; भारत पर गहरे विभाजित बहुध्रुवीय विश्व में स्थिरता लाने का उत्तरदायित्व है। प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने अपनी टिप्पणी में बताया कि दुनिया अभूतपूर्व संकट से गुजर रही है। अधिक से अधिक देश संकट में शामिल हो रहे हैं। शरणार्थियों और पलायन का संकट भी बढ़ता जा रहा है। सार्वजनिक स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, मंदी और मुद्रास्फीति में अनिश्चितता शामिल है। सतत विकास लक्ष्यों (महानिदेशक) के पूरे एजेंडे में 7-8 वर्ष की देरी हो रही है। जी-20 सहित सभी बहुपक्षीय रूप तीन 3सी: कोविड-19, संघर्ष और जलवायु से जूझ रहे हैं। वित्तीय संकट के विचार को ट्रिगर्स को हल किए बिना हल नहीं किया जा सकता है और ट्रिगर विकास को संबोधित करने की विफलता से आ रहे हैं। और यही कारण है कि सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों (एमडी) को पूरा करने के बाद, महानिदेशक के एजेंडे को अपनाया गया था। वैश्विक असमानता पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। भारतीय अध्यक्षता के लिए स्थानीय विकास लाना महत्वपूर्ण है और इसलिए इसे स्थानीय उत्पादन और स्थानीय क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित करना चाहिए।

डॉ. अंकिता दत्ता, अध्येता, भारतीय वैश्विक परिषद द्वारा लिखित सप्रू हाउस पेपर "क्यों विसेग्राद 4? - भारत-वी4 सहयोग की संभावनाएं, शोध-पत्र पर चर्चा, 22 अगस्त 2022

भारतीय वैश्विक परिषद ने 22 अगस्त 2022 को डॉ. अंकिता दत्ता द्वारा लिखित सप्रू हाउस पेपर पर एक चर्चा का आयोजन किया जिसका शीर्षक था "क्यों विसेग्राद 4? - भारत-वी 4 सहयोग की संभावनाएं। चर्चा की अध्यक्षता जेएनयू के सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज की प्रोफेसर प्रोफेसर भास्वती सरकार ने की और चर्चा करने वालों में दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. धनंजय त्रिपाठी और जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉ. जे जेगनथन शामिल थे। शोध-पत्र भारत और विसेग्राद 4 (पोलैंड, हंगरी, चेक गणराज्य और स्लोवाकिया) देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और हाल के वर्षों में उनके विकास को देखता है और सहयोग के पारंपरिक और साथ ही नए क्षेत्रों को चिह्नित करता है।

राजदूत शाहिदुल हक, पूर्व विदेश सचिव, बांग्लादेश द्वारा "बांग्लादेश विदेश नीति" पर विशेष व्याख्यान, 23 अगस्त 2022

भारतीय वैश्विक परिषद ने 23 अगस्त 2022 को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश के पूर्व विदेश सचिव राजदूत शाहिदुल हक द्वारा "बांग्लादेश विदेश नीति" पर एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया। विशेष व्याख्यान की अध्यक्षता जी-20 के मुख्य समन्वयक और पूर्व विदेश सचिव श्री हर्षवर्धन श्रृंगला ने की।

भारतीय वैश्विक परिषद की महानिदेशक राजदूत विजय ठाकुर सिंह ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि व्याख्यान विशेष है क्योंकि यह चार कारणों से महत्वपूर्ण समय पर हो रहा है। सबसे पहले, भारत और बांग्लादेश ने 2021 में अपने राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया। मैत्री दिवस नई दिल्ली और ढाका के अलावा दुनिया की 18 राजधानियों में संयुक्त रूप से मनाया गया। दूसरा, यह तब हो रहा है जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा है, 'आजादी का अमृत महोत्सव' की थीम पर। भारत के लिए, पड़ोसी प्रथम अपनी विदेश नीति में एक प्राथमिकता है और बांग्लादेश का एक महत्वपूर्ण स्थान है। तीसरा, अपने अस्तित्व के पिछले पचास वर्षों में,

बांग्लादेश ने लचीलापन दिखाया है और एक राष्ट्र-राज्य की दृढ़ नींव रखी है। बांग्लादेश का निर्माण बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान द्वारा तैयार किए गए दृष्टिकोण पर किया गया था, जो एक असाधारण राजनीतिक दूरदर्शी और लोगों के एक करिश्माई नेता थे, जिन्होंने राष्ट्र के लिए एक स्वतंत्र विदेश नीति बनाई थी। चौथा, यह व्याख्यान प्रधानमंत्री शेख हसीना की आगामी नई दिल्ली यात्रा से ठीक पहले हो रहा है, जो बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों को और सुदृढ़ करेगा।

श्री हर्षवर्धन श्रृंगला ने अध्यक्ष के रूप में अपने उद्घाटन भाषण में, कहा कि व्याख्यान एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आयोजित किया जा रहा है – बांग्लादेश ने अभी-अभी स्वतंत्रता के 50 वर्ष मनाए हैं, भारत-बांग्लादेश ने द्विपक्षीय संबंधों के 50 वर्ष मनाए हैं; बंगबंधु की 100वीं जयंती मना रहा है बांग्लादेश; और भारत आजादी के 75 वर्ष मना रहा है और अगले 25 वर्ष अमृत काल का हिस्सा हैं क्योंकि भारत आजादी के 100 वर्ष की ओर बढ़ रहा है। 2008 के बाद से दोनों देशों के बीच संबंध जबरदस्त गति से विकसित हुए हैं। 2008 में प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता में आते ही उन्होंने बांग्लादेश से उन विद्रोहियों को निष्कासित कर दिया है जो भारत के विरुद्ध काम कर रहे थे। अपनी ओर से, भारत ने ढाका को शुल्क मुक्त बाजार पहुंच प्रदान की है और इसके विकास के लिए सॉफ्ट लोन प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि साझेदारों के बीच हस्ताक्षरित दो प्रमुख समझौतों में भूमि सीमा समझौता और समुद्री सीमा का परिसीमन शामिल है। संबंधों के महत्व को इस तथ्य से और अधिक उजागर किया जाता है कि पिछले वर्ष में ही भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने बांग्लादेश का दौरा किया है। संबंधों में प्रमुख विकास में भारत और बांग्लादेश के बीच रेल और सड़क संपर्क की बहाली; अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास; रक्षा क्षेत्र में फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर; आर्थिक एकीकरण की सुविधा के लिए गैर-टैरिफ बाधाओं को हटाना; लोगों से लोगों के संपर्क की क्षमता जारी करना; भारत से बांग्लादेश के लिए ऑक्सीजन ट्रेनों और वैक्सीन मैत्री के तहत टीकों के माध्यम से महामारी के दौरान सहयोग शामिल है। आगे बढ़ने के लिए श्री श्रृंगला ने कहा कि दोनों देशों के युवाओं पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। व्यापक व्यापार समझौते का समापन; समुद्री सहयोग; फिनटेक और आईओटी; तृतीय पक्ष बिजली आपूर्ति प्रणाली; बिम्सटेक और बीबीआईएन जैसे क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय संगठनों में सहयोग बढ़ाना; और निजी क्षेत्र के निवेश में वृद्धि हुई।

राजदूत शाहिदुल हक ने अपने विशेष व्याख्यान में कहा कि 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश खस्ताहाल हो गया था और 30 प्रतिशत से अधिक आबादी गरीबी में जी रही थी। हालांकि, बांग्लादेश ने तेजी से विकास और सामाजिक आर्थिक विकास के साथ इस स्थिति से उबर गया है। कोविड महामारी के दौरान, बांग्लादेश ने स्थिर वृद्धि और मध्यम मुद्रास्फीति का अनुभव किया। उच्च जीडीपी वृद्धि के बावजूद, रोजगार वृद्धि लगभग 1 प्रतिशत पर कम रही है। महामारी के कारण बेरोजगारी दर बढ़ी है और 5 प्रतिशत से ऊपर बनी हुई है। बांग्लादेश की विदेश नीति के मूल सिद्धांतों में शामिल हैं - संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के प्रति प्रतिबद्धता और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग में योगदान देना; राष्ट्रीय संप्रभुता और समानता के लिए सम्मान; अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना; अंतरराष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के लिए सम्मान। बांग्लादेश की विदेश नीति के तत्वों में संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, सुरक्षा और राष्ट्रीय हित की रक्षा करना; मुक्ति संग्राम और संविधान के मूल्यों को बनाए रखना; शांति, स्थिरता और सतत विकास (शोनार बांग्ला); राष्ट्रीय हित की प्राप्ति; व्यावहारिकता और नवाचार; मानवतावाद और मानवाधिकार; और एक प्रतिस्पर्धी और राष्ट्रीय हित-संचालित दुनिया में गठबंधन और सहयोगियों का निर्माण करना शामिल है। बांग्लादेश की विदेश नीति की ताकत में उसका भूगोल, जनसांख्यिकी, अर्थव्यवस्था, कनेक्टिविटी, प्रौद्योगिकी और रक्षा शामिल हैं। जबकि सीमाओं में जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं से उपजे खतरे, हिंसक चरमपंथ का उदय,

दस लाख से अधिक रोहिंग्याओं की उपस्थिति और शासन की सीमाएं शामिल हैं। बांग्लादेश की विदेश नीति में भारत एक महत्वपूर्ण साझेदार बना हुआ है। भारत और बांग्लादेश के लोगों के बीच संबंध त्रासदी, बलिदान, संकट के साथ-साथ प्रेरणा, स्वतंत्रता, विविधता, विकास और समावेश की एक अनूठी स्थिति में बने हैं। बांग्लादेश की हिंद-प्रशांत रणनीति कानून के शासन को बढ़ावा देने और स्थापित करने, नेविगेशन की स्वतंत्रता, मुक्त व्यापार आर्थिक समृद्धि का पीछा; और शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्धता आदि से प्रेरित है। बांग्लादेश की विदेश नीति के लिए प्रमुख चुनौतियां हैं - बढ़ती तनाव, दरार और बड़ी शक्तियों के बीच और उनके बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा; अंतर-राज्य और अंतर-समाज संबंधों में गैर-राज्य नायकओं की भागीदारी; पारंपरिक 'उच्च मुद्दे' विदेश नीति से परे सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में जुड़ाव बढ़ाना; क्षेत्रीय/अंतर-क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय सहयोग पर बढ़ता फोकस; राजनयिक प्रथाओं के तंत्र और मशीनरी को बदलना (एआई सक्षम उपकरण); राज्य हित और लोगों की आकांक्षाओं के बीच संतुलन।

"एशिया में अमेरिकी विस्तारित परमाणु निवारण" पर गोलमेज चर्चा, 25 अगस्त 2022

भारतीय वैश्विक परिषद ने 25 अगस्त 2022 को "एशिया में अमेरिकी विस्तारित परमाणु निवारण" पर एक गोलमेज परिचर्चा का आयोजन किया। वार्ता की अध्यक्षता राजदूत शीलकांत शर्मा, वियना में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय और आईएईए के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि ने की। वक्ताओं में सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज, नई दिल्ली में प्रतिष्ठित अध्येता डॉ. मनप्रीत सेठी; चिंतामणि महापात्रा, पूर्व प्रोफेसर, स्कूल फॉर इंटरनेशनल स्टडीज, जेएनयू; और प्रोफेसर राजेश राजगोपालन, प्रोफेसर, स्कूल फॉर इंटरनेशनल स्टडीज, जेएनयू थे।

"पाकिस्तान के निरंतर राजनीतिक और आर्थिक संकट" पर पैनल चर्चा, 30 अगस्त 2022

भारतीय वैश्विक परिषद ने 30 अगस्त 2022 को सप्रू हाउस में "पाकिस्तान के सतत राजनीतिक और आर्थिक संकट" पर एक पैनल चर्चा का आयोजन किया। चर्चा का संचालन अफगानिस्तान, म्यांमार और थाईलैंड में भारत के पूर्व राजदूत विवेक काटजू ने किया। दो पैनलिस्ट प्रोफेसर अजय दर्शन बेहरा, एकेडमी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय; और डॉ. अशोक के बेहुरिया, वरिष्ठ अध्येता, एमपी-आईडीएसए थे।

भारतीय वैश्विक परिषद की महानिदेशक राजदूत विजय ठाकुर सिंह ने कहा कि पाकिस्तान कई जटिल और आपस में जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। पाकिस्तान में हालिया बाढ़ ऐसे समय आई है जब देश पहले से ही राजनीतिक मंथन और आर्थिक संकट से गुजर रहा था। राजनीतिक पक्ष की बात करें तो जब से इमरान खान विश्वास मत हार गए हैं, वह राजनीतिक रैलियां और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और पंजाब और सिंध दोनों में उपचुनाव जीते हैं; जो पाकिस्तान में उनकी निरंतर लोकप्रियता

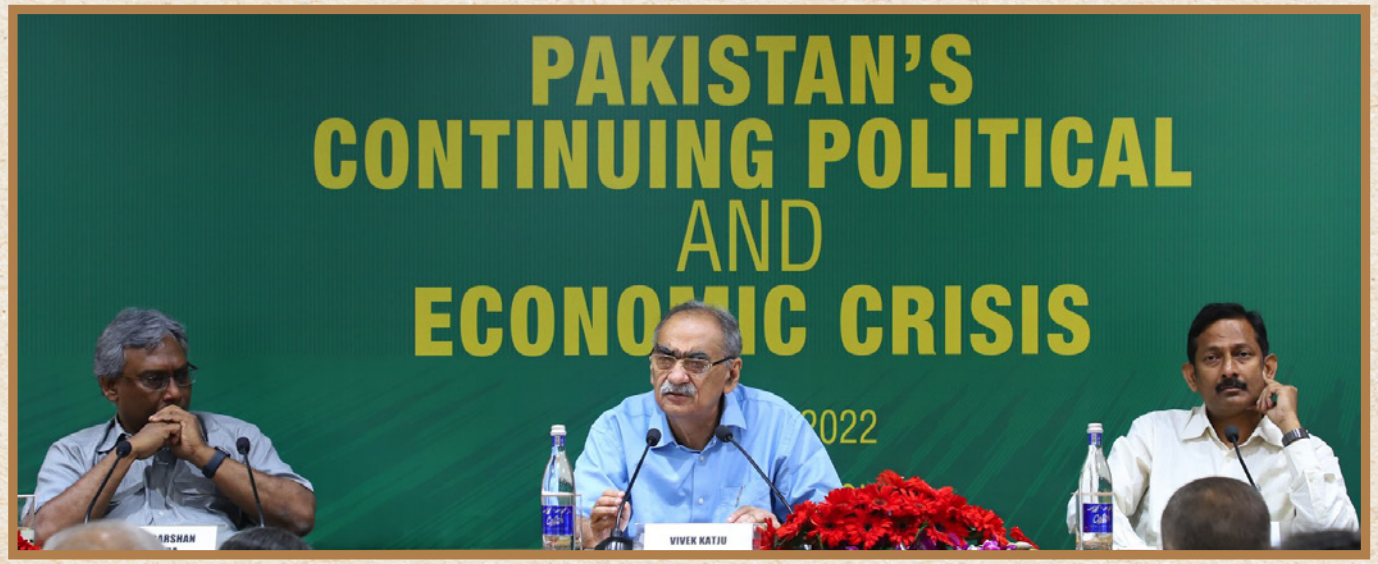

को दर्शाता है। उन्होंने प्रश्न उठाया कि पाकिस्तान की राजनीतिक गतिशीलता में 'इमरान कारक' का क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली बहुदलीय गठबंधन सरकार को मौजूदा आर्थिक संकट और बाढ़ से हुए नुकसान से निपटने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा गठबंधन सरकार पारंपरिक रूप से विरोधी दलों से बनी है जो इस गठबंधन के स्थायित्व पर सवालिया निशान लगाती है। आर्थिक मोर्चे पर पाकिस्तान ने बेलआउट के लिए आईएमएफ से संपर्क किया था। इसने निवेश के लिए सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे अन्य देशों से भी संपर्क किया - क्या आईएमएफ और अन्य देशों का समर्थन पाकिस्तान की मैक्रो-आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने का प्रबंधन करेगा, यह देखा जाना बाकी है। उन्होंने आगे कहा कि आतंकवाद का समर्थन करने में पाकिस्तान की भूमिका चिंता का विषय है। यह एक महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा लगातार नजर रखी जा रही है।

राजदूत विवेक काटजू ने अपने उद्घाटन भाषण के दौरान कहा कि पाकिस्तान एक चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है; हालांकि, पाकिस्तान के इतिहास में यह पहली बार नहीं है जब उसे इस तरह की अशांति का सामना करना पड़ा है। जैसा कि पाकिस्तान अपनी स्थापना की 75 वीं वर्षगांठ मना रहा है, अतीत से सीखे गए सबक का आकलन करने की आवश्यकता है। देश आत्मनिरीक्षण के दौर से गुजरा जब उसने 1972 में 25 वर्ष पूरे किए, जो पूर्वी पाकिस्तान के पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश के एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरने के ठीक बाद हुआ था। उस आत्मनिरीक्षण के कारण भारत विरोधी स्थिति सख्त हो गई। इस तरह के रुख के कारण पाकिस्तान ने परमाणु हथियार विकसित करने का निर्णय भी किया। राजदूत काटजू ने कहा कि उन्हें भविष्य में ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आती कि पाकिस्तान भीतर से आवाज सुने जो भौगोलिक राष्ट्रवाद के बजाय धार्मिक राष्ट्रवाद के आधार पर राज्य को आधार बनाने के उद्यम को छोड़ने का आग्रह कर रहे हैं। पाकिस्तान उन रणनीतियों का कोई लागत लाभ विश्लेषण भी नहीं कर रहा है, जो उसने अपनाई हैं, विशेषकर तीन दशकों से अधिक समय से भारत के विरुद्ध आतंकवाद। इस दौरान पाकिस्तान के मानव विकास सूचकांक में काफी गिरावट आई है।

प्रोफेसर अजय दर्शन बहेरा (एकेडमी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय) ने कहा कि पाकिस्तान का संकट में होना कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान इस समय राजनीतिक और आर्थिक दोनों तरह के गहरे संरचनात्मक संकट का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान में मौजूद सत्ता संरचना के लिए पाकिस्तान में सैन्य और राजनीतिक अभिजात वर्ग उत्तरदायी हैं। पाकिस्तान के सामने आने वाली चुनौतियों के कुछ कारणों और नई गतिशीलता की पहचान करना महत्वपूर्ण है। मौजूदा चुनौतियां 2014 में पेशावर आर्मी स्कूल में हुए आतंकवादी हमले के बाद से शुरू हुई थीं। इसने आम जनता पर गहरा प्रभाव डाला, सेना के बारे में लोगों की धारणा को बदल दिया। ऐसी भावना या धारणा थी कि सेना अपने लोगों को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) जैसे समूहों के साथ सेना के संबंधों के बारे में प्रश्न उठाए गए थे। प्रोफेसर बेहरा ने कहा कि इमरान खान के उदय ने पाकिस्तानी राजनीति में कुछ नई गतिशीलता लाई है। पेशावर आर्मी स्कूल हमले का पाकिस्तानी मानस पर गहरा असर पड़ा और यह इमरान खान के लिए एक रैली प्वाइंट बन गया। इससे पाकिस्तान में मतदाताओं में बदलाव हुआ-राष्ट्रीय स्तर पर पीटीआई के उदय के साथ दो प्रमुख दलों के प्रभुत्व वाली राजनीति से तीन प्रमुख दलों में।

अगले चर्चाकर्ता डॉ. अशोक के बेहुरिया ने कहा कि पाकिस्तान संकट का आदी है-यह एक संकट से पैदा हुआ था, पिछले सात दशकों में कई राजनीतिक और आर्थिक संकट का सामना किया और वर्तमान में इस तरह के संकट का सामना करना पड़ रहा है। डॉ. बेहुरिया ने अपनी राय साझा की कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति उतनी गंभीर नहीं है जितनी दिखती है। पाकिस्तान में एक बहुत विकसित अनौपचारिक अर्थव्यवस्था है जो मैक्रो-इकोनॉमिक झटकों को अवशोषित करती है। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तानी सेना को देश में राजनीतिक परिदृश्य पर हावी होने के लिए अपनी नीतियों को लगातार बदलना होगा और पाकिस्तानी सेना को पाकिस्तान में एक अलग राजनीतिक इकाई के रूप में माना जा सकता है जो चुनाव नहीं लड़ती है लेकिन प्रासंगिक बनी हुई है।

यू मिन ज़िन, संस्थापक सदस्य और कार्यकारी निदेशक, इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजी एंड पॉलिसी, म्यांमार द्वारा "म्यांमार में स्थिति" पर वार्ता, 5 सितंबर, 2022

भारतीय वैश्विक परिषद ने 5 सितंबर 2022 को 'म्यांमार में स्थिति' पर एक वार्ता का आयोजन किया, जिसमें संस्थापक सदस्य और कार्यकारी निदेशक, इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजी एंड पॉलिसी, म्यांमार शामिल थे। इस वार्ता में विशेषज्ञों, विद्वानों और मीडिया प्रतिनिधियों का एक चुनिंदा समूह मौजूद था, जिसके बाद चर्चा हुई। भारतीय वैश्विक परिषद की महानिदेशक राजदूत विजय ठाकुर सिंह ने वार्ता की अध्यक्षता की। फरवरी 2021 के तख्तापलट के बाद म्यांमार की स्थिति, वर्तमान क्षेत्रीय और वैश्विक भू-राजनीति, चीन की भूमिका, म्यांमार समाज का सैन्यीकरण, भारत के साथ संबंध और म्यांमार के लिए परिदृश्यों पर चर्चा की गई।

"हिंद महासागर में भारत और द्वीप राज्य: भू-राजनीति और सुरक्षा परिप्रेक्ष्य विकसित करना" पर भारतीय वैश्विक परिषद् वेब आधारित सम्मेलन, 6 सितंबर 2022

भारतीय वैश्विक परिषद ने 6 सितंबर 2022 को 'हिंद महासागर में भारत और द्वीप राज्य: विकसित भूराजनीति और सुरक्षा परिप्रेक्ष्य' पर एक ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। संगोष्ठी के वक्ताओं में हिंद महासागर द्वीप राष्ट्रों और भारत के विदेश नीति और रणनीतिक विशेषज्ञ शामिल थे। संगोष्ठी में भारत और अन्य देशों के राजनयिक, अकादमिक और रणनीतिक समुदाय के सदस्यों ने भाग लिया।
उद्घाटन सत्र में भारतीय वैश्विक परिषद् की महानिदेशक राजदूत विजय ठाकुर सिंह ने उद्घाटन भाषण दिया। उन्होंने भारत की विदेश और रणनीतिक नीति में हिंद महासागर और व्यापक हिंद-प्रशांत क्षेत्र के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि परिषद ने प्रमुख सम्मेलनों और नियमित प्रकाशनों की मेजबानी के माध्यम से इस विषय पर सक्रिय रूप से अनुसंधान किया है। यह संगोष्ठी अद्वितीय थी क्योंकि यह द्वीप राष्ट्रों

के रणनीतिक दृष्टिकोणों पर केंद्रित थी और उन्हें हिंद महासागर के प्रति भारत की विदेश नीति में स्थित करती थी। भारत के हिंद महासागर के द्वीपीय देशों के साथ पारंपरिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, उसने सुदृढ़ राजनीतिक, आर्थिक, विकासात्मक और लोगों से लोगों के बीच संबंध बनाए हैं और अपनी सागर (सभी के लिए सुरक्षा और विकास) पहल के हिस्से के रूप में उनके साथ मजबूती से जुड़ रहा है।

मुख्य भाषण भारतीय वैश्विक परिषद् के शासी निकाय के सदस्य डॉ. संजय बारू ने दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता बढ़ने और हिंद महासागर क्षेत्र में बाहरी शक्तियों की नए सिरे से रुचि बढ़ने से दुनिया प्रवाह की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि संगोष्ठी ऐसे समय में हो रही है जब भारत ने हाल ही में एक नया विमान कैरियर (आईएनएस विक्रांत) लॉन्च किया था और चीनी नौसेना का एक जहाज श्रीलंका गया था। यूरोपीय शक्तियों, विशेष रूप से ब्रिटेन और फ्रांस ने हिंद महासागर में नए सिरे से रुचि दिखाई है, पानी का यह निकाय जो 'शांति का क्षेत्र' बना हुआ है, वैश्विक ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया है। इसलिए, इस भौगोलिक क्षेत्र के भीतर के देशों के लिए यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि हिंद महासागर क्षेत्र में संघर्ष की एकमात्र स्मृति उन शक्तियों से जुड़ी हुई है जिन्होंने बाहर से इस स्थान में प्रवेश किया है। भारत इस क्षेत्र में कभी भी आधिपत्य वाली शक्ति नहीं रहा है। वास्तव में, इसने क्षेत्र के भीतर विकास और सुरक्षा को बढ़ावा देने की मांग की है। इसकी सागर पहल क्षेत्र के सभी देशों की सुरक्षा और विकासात्मक हितों को संतुलित करती है।

'श्रीलंका और मालदीव' पर पहले सत्र की अध्यक्षता श्रीलंका में पूर्व भारतीय उच्चायुक्त राजदूत (सेवानिवृत्त) अशोक कंठ ने की। सत्र के वक्ताओं में भू-राजनीतिक विश्लेषक, सुरक्षा पर रणनीतिक सलाहकार और लेखक, द मिलेनियम प्रोजेक्ट, वाशिंगटन डीसी (श्रीलंका) के वरिष्ठ अध्येता असांगा अबेयागूनासेकरा, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के प्रशांत मामलों के विभाग और विदेश मंत्रालय (मालदीव) के पूर्व राजनयिक अथौला ए रशीद, सेंटर फॉर ईस्ट एशियन स्टडीज के निदेशक एन. मनोहरन, अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर, क्राइस्ट विश्वविद्यालय, बैंगलोर (भारत) और वाइस एडमिरल (सेवानिवृत्त) एमपी मुरलीधरन, पूर्व महानिदेशक, भारतीय तटरक्षक बल थे।

पहले सत्र में श्रीलंका के वर्तमान राजनीतिक और आर्थिक संकट, हिंद महासागर भू-राजनीति पर इसके प्रभाव, क्षेत्र की सुरक्षा गतिशीलता और वर्तमान श्रीलंकाई संकट में 'चीन कारक' पर चर्चा की गई। जलवायु परिवर्तन सहित भू-राजनीतिक चुनौतियों पर मालदीव के दृष्टिकोण को साझा किया गया और विकास सहयोग में भारत की बढ़ती भूमिका पर जोर दिया गया। भारत की पड़ोसी प्रथम नीति के हिस्से के रूप में परस्पर लाभ की आशा के बिना भारत को 'पहला उत्तरदाता' बनने की तत्परता का उल्लेख किया गया। पैनलिस्टों ने क्षेत्र में विभिन्न शक्तियों की बदलती समुद्री रणनीतियों और तटवर्ती राष्ट्रों की रणनीतिक जटिलताओं जैसे मुद्दों पर बात की, जिन्हें मान्यता दी जानी चाहिए और समझा जाना चाहिए। इस बात पर प्रकाश डाला गया कि हिंद महासागर क्षेत्र को अलग-थलग करके नहीं देखा जा सकता है क्योंकि यह एशियाई आर्थिक विकास, वैश्वीकरण की प्रक्रिया के साथ रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है और प्रभावित होता है। टकराव और शून्य-योग परिणामों से बचने के महत्व पर जोर दिया गया।

'दक्षिण-पश्चिम हिंद महासागर में द्वीप राज्य' पर दूसरे सत्र की अध्यक्षता राजदूत अनूप मु, महानिदेशक (सेवानिवृत्त) मॉरीशस में पूर्व भारतीय

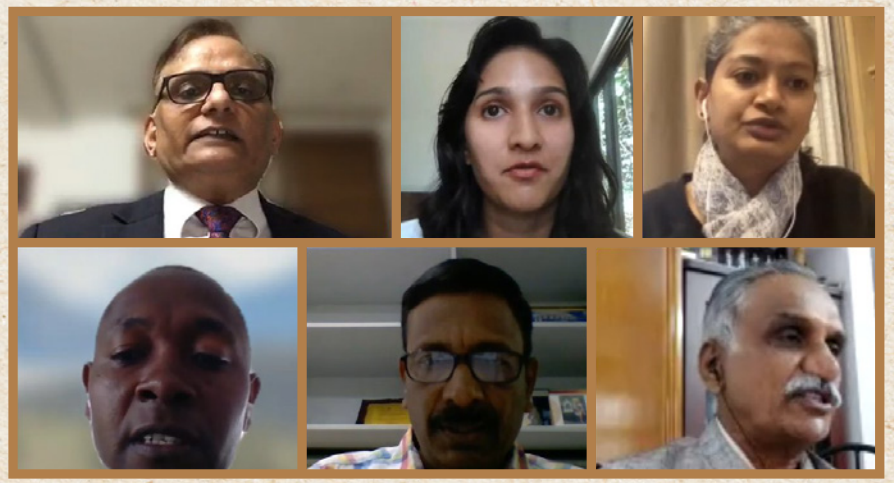

उच्चायुक्त ने की। सत्र के पैनलिस्टों में सेशेल्स विश्वविद्यालय (सेशेल्स) के व्यापार और सतत विकास संकाय की सहायक विभागाध्यक्ष सुश्री मालशिनी सेनारत्ने, मॉरीशस विश्वविद्यालय (मॉरीशस) के सामाजिक विज्ञान और मानविकी संकाय की व्याख्याता डॉ. प्रिया बहादुर, मेडागास्कर (मेडागास्कर) के टोमासिना विश्वविद्यालय के व्याख्याता डॉ. जुवेंस रामासी, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के डीन प्रोफेसर ए. सुब्रमण्यम राजू शामिल थे। पांडिचेरी विश्वविद्यालय (भारत) और कमोडोर (सेवानिवृत्त) आरएस वासन, महानिदेशक, चेन्नई सेंटर फॉर चाइना स्टडीज (भारत) थे।

दूसरे सत्र में विशेष आर्थिक क्षेत्रों (ईईजेड) को सुरक्षित और दोहन करने के लिए दीर्घकालिक रणनीतियों के साथ-साथ हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) की सुरक्षा सुनिश्चित करने की रणनीतियों पर चर्चा की गई। महासागर की सुरक्षा और संरक्षा के लिए क्षेत्रीय और अतिरिक्त क्षेत्रीय शक्तियों के साथ तकनीकी सहयोग पर जोर दिया गया। चर्चा का एक अन्य मुख्य बिन्दु समुद्री अर्थव्यवस्था का मुद्दा था जो द्वीपयी देशों के विकास और सुरक्षा हितों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है। सागर के तहत सॉफ्ट पावर और नौसेना कूटनीति, एचएडीआर गतिविधियों और स्वास्थ्य, संस्कृति और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहायता सहित क्षेत्र में भारत के दृष्टिकोण पर भी चर्चा की गई। यह नोट किया गया कि समुद्री आयाम ने सुरक्षा के क्षेत्र सहित एक पसंदीदा भागीदार के रूप में भारत की विश्वसनीयता को बढ़ाया है। भारतीय पैनलिस्टों ने बताया कि कैसे यह क्षेत्र भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है।

आईसीसीआर के जेन-नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क प्रोग्राम के विदेशी प्रतिनिधियों के 5वें सत्र के साथ चर्चा, 7 सितंबर 2022

भारतीय वैश्विक परिषद ने 7 सितंबर 2022 को सप्रू हाउस में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) के जनरल-नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क प्रोग्राम के विदेशी प्रतिनिधियों की मेजबानी की। चर्चा की अध्यक्षता भारतीय वैश्विक परिषद् के महानिदेशक राजदूत विजय ठाकुर सिंह ने की। चर्चा में भाग लेने वाले प्रतिनिधि रोमानिया, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, दक्षिण कोरिया, कोस्टा रिका और ऑस्ट्रिया से थे। भारतीय वैश्विक परिषद् के उप महानिदेशक श्री सौमेन बागची ने विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के मुद्दों पर भारत के विमर्श को बढ़ावा देने में भारतीय वैश्विक परिषद् के विकास और अधिदेश पर प्रकाश डाला। भारतीय वैश्विक परिषद् की महानिदेशक राजदूत विजय ठाकुर सिंह ने भारतीय विदेश नीति पर एक सिंहावलोकन दिया। भारतीय वैश्विक परिषद् के अनुसंधान संकाय सदस्यों ने यूक्रेन संकट, चीन, अफगानिस्तान और हिंद-प्रशांत क्षेत्रों जैसे वर्तमान वैश्विक व्यवस्था को आकार देने वाले भू-राजनीतिक मुद्दों पर अपनी अंतर्दृष्टि साझा की।

भारत-पेरू संबंधों पर भारतीय वैश्विक परिषद-पीयूसीपी, लीमा संवाद: क्षेत्र और द्विपक्षीय संबंधों के साथ जुड़ाव, 8 सितंबर 2022

भारतीय वैश्विक परिषद और इसके समझौता ज्ञापन साझेदार पोंटिफिकल कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ पेरू (पीयूसीपी), लीमा ने 8 सितंबर 2022 को भारत-पेरू संबंध: क्षेत्र के साथ जुड़ाव और द्विपक्षीय संबंध विषय पर अपना उद्घाटन संवाद ऑनलाइन आयोजित किया।

संवाद के उद्घाटन सत्र में भारतीय वैश्विक परिषद् की महानिदेशक राजदूत विजय ठाकुर सिंह, पेरू में भारत के राजदूत श्री एम. सुब्बरायुडू, पेरू, भारत के दूतावास की चारगे डी अफेयर्स सुश्री मोनिका कैंपोस और पीयूसीपी के अनुसंधान उपाध्यक्ष डॉ. एल्दो पनफीची ने टिप्पणी की।

भारतीय वैश्विक परिषद की महानिदेशक राजदूत विजय ठाकुर सिंह ने कहा कि लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई (एलएसी) क्षेत्र भारत के लिए बढ़ता महत्व का है। यह क्षेत्र संसाधनों और खनिजों से समृद्ध है, प्रभावशाली कृषि और विनिर्माण है और भारत की खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा जरूरतों में भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत एक सुदृढ़ और अग्रणी लोकतंत्र है, पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और एक आकांक्षी राष्ट्र है जो प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष अनुसंधान में अग्रणी है और उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में विश्व स्तरीय कंपनियां हैं जहां भारत और लैटिन अमेरिका के देश संयुक्त सहयोग और निवेश का पता लगा सकते हैं। उन्होंने क्षेत्र में भारत की उच्च स्तरीय यात्राओं पर प्रकाश डाला और कहा कि भारत डोमिनिकन गणराज्य और पराग्वे में दूतावासों के साथ क्षेत्र में अपनी राजनयिक उपस्थिति का विस्तार कर रहा है, जिनका हाल ही में उद्घाटन किया गया था।

पीयूसीपी के अनुसंधान उपाध्यक्ष डॉ. एल्डो पनफिकी ने पीयूसीपी, लीमा के मूल्य और मिशन के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय भारतीय वैश्विक परिषद् जैसे संस्थानों के साथ अपनी साझेदारी के माध्यम से एशिया और भारत के अपने ज्ञान महानिदेशकों का विस्तार करना चाहता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और विदेश मामलों में बुद्धिजीवियों और विशेषज्ञों के बीच चर्चा से भारत और पेरू के बीच और लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र और भारत के बीच संबंधों को विकसित करने में मदद मिलेगी। पेरू के एक अग्रणी विश्वविद्यालय के रूप में, पीयूसीपी अपने विद्वानों के बीच भारत और एशिया के बारे में एक ज्ञात निदेशक जनरल आधार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

पेरू में भारत के राजदूत एम. सुब्बारायुडू ने दोनों देशों के बीच छह दशक से अधिक समय से चले आ रहे सौहार्दपूर्ण संबंधों का उल्लेख किया। ये संबंध सांस्कृतिक आत्मीयता और लोगों के बीच बढ़ते संपर्कों द्वारा चिह्नित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश बहुसांस्कृतिक प्राचीन सभ्यताएं हैं जो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करते हैं और जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई, भूख और गरीबी उन्मूलन जैसी साझा चिंताओं को साझा करते हैं। भारत और पेरू दक्षिण-दक्षिण सहयोग में भागीदार हैं और बहुपक्षीय मंचों पर मिलकर काम करते हैं। उन्होंने दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापार संबंधों का उल्लेख किया और विशेष रूप से अंतरिक्ष, ऊर्जा, रक्षा और उच्च प्रौद्योगिकी जैसे प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अधिक पूरकताओं का पता लगाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान, भारत ने कोविड दवा प्रौद्योगिकियां और तकनीक आधारित वस्तुएं और सेवाएं प्रदान की थीं। विविध संबंध रक्षा और अंतरिक्ष, आईटी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, शिक्षा और पारंपरिक चिकित्सा जैसे क्षेत्रों को कवर करते हैं।

सुश्री मोनिका कैम्पोस, चार्गे डी अफेयर्स, पेरू दूतावास ने कहा कि दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध सुदृढ़ है और बढ़ रहे हैं, लेकिन उनमें अधिक क्षमता है। उन्होंने कहा कि पेरू की कई कंपनियां हैं जो भारत में खनन क्षेत्र में निवेश कर रही हैं। व्यापार के पारंपरिक क्षेत्र जैसे कि सोने और तांबे जैसे खनिज महत्वपूर्ण बने हुए हैं। साथ ही, निजी उद्योग एक-दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं में निवेश करने के लिए कदम उठा रहे हैं, जिससे व्यापार में विविधता आ रही है। उन्होंने कहा कि पेरू कृषि और कृषि-औद्योगिक क्षेत्र में भारत के साथ अवसरों का पता लगाना चाहता है।

भारत-पेरू संबंध: क्षेत्र के साथ जुड़ाव और द्विपक्षीय संबंधों पर पैनल चर्चा की अध्यक्षता पीयूसीपी के अनुसंधान उपाध्यक्ष के सलाहकार प्रोफेसर रुबिन तांग ने की। पैनल में वक्ताओं में राजदूत रवि थापर, पनामा, कोस्टा रिका और निकारागुआ में भारत के पूर्व राजदूत और इंडोनेशिया में पेरू के राजदूत लुइस त्सुबोयामा शामिल थे। उन्होंने लैटिन अमरीका के साथ भारत के जुड़ाव और एशिया के साथ पेरू के संबंधों पर चर्चा की। उन्होंने अमेरिका-चीन टकराव, ताइवान क्रॉस-स्ट्रेट तनाव, कोविड-19 महामारी और यूक्रेन संकट सहित वर्तमान भू-राजनीतिक परिदृश्य को परिभाषित करने वाले प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय रुझानों पर चर्चा की। उन्होंने भारत और क्षेत्र के बीच आर्थिक संबंधों पर भी चर्चा की। गरीबी उन्मूलन और डिजिटलीकरण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में अनुभवों और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान की संभावना और विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में पेरू और इस क्षेत्र में भारत द्वारा उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना पर चर्चा की गई। बेहतर बी 2 बी इंटरैक्शन के लिए आवश्यक प्रयासों पर जोर दिया गया।

लीमा के पीयूसीपी के राजनीति विज्ञान विभाग के प्रमुख डॉ. सेबेस्टियन अदिन्स और भारतीय वैश्विक परिषद्, नई दिल्ली की अध्येता डॉ. स्तुति बनर्जी ने भारत-पेरू द्विपक्षीय संबंधों पर अपने विचार व्यक्त किए। द्विपक्षीय संबंधों के छह दशकों का अवलोकन प्रस्तुत किया गया था; इस बात पर जोर दिया गया कि दोनों देशों में बहुसंस्कृतिवाद, वैश्विक दक्षिण की एकजुटता आदि में साझा विश्वासों के आधार पर बहुपक्षीय में एक साथ काम करने की परंपरा रही है। इस बात पर जोर दिया गया कि व्यापार और अर्थशास्त्र द्विपक्षीय संबंधों का मुख्य आधार हैं और भारत पेरू का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बन गया है। खनन, कृषि, खनिज व्यापार जैसे अर्थव्यवस्था के पारंपरिक क्षेत्रों में साझेदारी का उल्लेख किया गया, स्टार्ट-अप, एआई, जलवायु परिवर्तन पहल और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे सहयोग के संभावित भविष्य के क्षेत्रों पर चर्चा की गई।

वार्ता में कहा गया कि भारत और पेरू 2023 में अपने राजनयिक संबंधों के 60 वें वर्ष का जश्न मनाएंगे। इसने संबंधों का जायजा लेने, आगे का रास्ता तय करने और समग्र संबंधों को गति देने का अवसर प्रदान किया।

भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ द्वारा कार्यभार संभालने के बाद भारतीय वैश्विक परिषद के महानिदेशक राजदूत विजय ठाकुर सिंह ने 10 सितंबर 2022 को उनसे भेंट की।

भारतीय वैश्विक परिषद के अध्येता डॉ. श्रीपति नारायणन द्वारा लिखित "क्रा के इस्तमुस: रेल और नहर द्वारा मलय प्रायद्वीप को जोड़ना" पर सप्रू हाउस पेपर (एसएचपी) चर्चा, 13 सितंबर 2022

भारतीय वैश्विक परिषद के अध्येता डॉ. श्रीपति नारायणन द्वारा 'क्रा के इस्तमुस: रेल और नहर द्वारा मलय प्रायद्वीप को जोड़ना' विषय पर सप्रू हाउस पेपर चर्चा का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (आरआईएस) के प्रोफेसर और आरआईएस में आसियान-भारत केन्द्र (एआईसी) के समन्वयक डॉ. प्रबीर डे ने की। आमंत्रित चर्चाकारों में एन के कुमारेसन राजा, प्रोफेसर और प्रमुख, राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन विभाग, पांडिचेरी विश्वविद्यालय, और, डॉ. अल्वाइट निंगथौजम, सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में सहायक प्रोफेसर थे।

हिंद महासागर रिम अकादमिक समूह (आईओआरएजी) की 27 वीं बैठक, 14 सितंबर 2022

हिंद महासागर रिम अकादमिक समूह (आईओआरएजी) की 27 वीं बैठक 14 सितंबर 2022 को वर्चुअल रूप से आयोजित की गई थी। भारतीय वैश्विक परिषद की निदेशक अनुसंधान डॉ. निवेदिता रे और भारतीय वैश्विक परिषद की अध्येता डॉ. प्रज्ञा पांडे ने भारतीय वैश्विक परिषद् के प्रतिनिधियों के रूप में बैठक में भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता प्रोफेसर जूलियट हर्मीस, एनआरएफ- सैन, दक्षिण अफ्रीका (वर्तमान आईओआरएजी अध्यक्ष) ने की। आईओआरएजी कार्य योजना 2022-2027 और आईओआरए-जीआईजेड जलवायु परिवर्तन परियोजना पर विचार-विमर्श किया गया। आईओआरए में अकादमिक-नीति इंटरफेस और जल विज्ञान को सुदृढ़ करने पर तकनीकी सत्र आयोजित किए गए थे।

डॉ. लक्ष्मी प्रिया, अध्येता, भारतीय वैश्विक परिषद, द्वारा लिखित "छोटे खाड़ी राष्ट्रों की बदलती विदेश नीति: संयुक्त अरब अमीरात का एक केस स्टडी" पर सप्रू हाउस पेपर (एसएचपी) चर्चा, 15 सितंबर 2022

भारतीय वैश्विक परिषद ने 15 सितंबर 2022 को भारतीय वैश्विक परिषद की अध्येता डॉ. लक्ष्मी प्रिया द्वारा 'छोटे खाड़ी देशों की बदलती विदेश नीति: संयुक्त अरब अमीरात का एक केस स्टडी' विषय पर सप्रू हाउस पेपर चर्चा का आयोजन किया। इसकी अध्यक्षता जॉर्डन, लीबिया और माल्टा के पूर्व राजदूत राजदूत अनिल त्रिगुणायत ने की। पूर्व निदेशक, खाड़ी प्रभाग, विदेश मंत्रालय; प्रतिष्ठित अध्येता, वीआईएफ। द हिंदू के एसोसिएट एडिटर अतुल अनेजा और अनवर गर्गश डिप्लोमैटिक एकेडमी, अबू धाबी के गल्फ एशिया कार्यक्रम के वरिष्ठ अध्येता डॉ. एन जनार्दन ने शोध-पत्र पर चर्चा की।

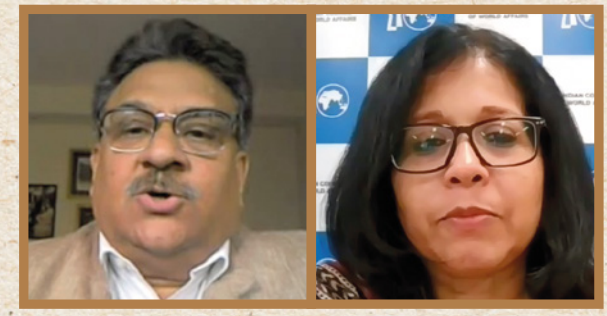

"दक्षिण चीन सागर में रणनीतिक प्रतिस्पर्धा: हित, रक्षा और कूटनीति" पर भारतीय वैश्विक परिषद्- इंडिया फ्यूचर फाउंडेशन संगोष्ठी, 16 सितंबर 2022

भारतीय वैश्विक परिषद ने इंडियन फ्यूचर्स के सहयोग से 16 सितंबर 2022 को 'दक्षिण चीन सागर में रणनीतिक प्रतियोगिता: हित, रक्षा और कूटनीति' पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। संगोष्ठी को दो सत्रों में विभाजित किया गया था: सत्र I: वैचारिक परिप्रेक्ष्य: खेल की स्थिति? और सत्र II: राज्य परिप्रेक्ष्य: गठबंधन, गुटनिरपेक्षता, या बहु-संरेखण?

भारतीय वैश्विक परिषद की महानिदेशक राजदूत विजय ठाकुर सिंह ने अपने स्वागत भाषण में दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बारे में विस्तार से बताया, जिसका हिंद-प्रशांत क्षेत्र और उससे परे देशों के लिए बहुत रणनीतिक और आर्थिक मूल्य है। चीन ने समय के साथ दक्षिण चीन सागर में अपनी गतिविधियां लगातार तेज कर दी हैं क्योंकि संसाधनों की उसकी जरूरतें बढ़ गई हैं और उसने अपने ऐतिहासिक समुद्री क्षेत्रीय दावों पर जोर दिया है। चीन के दावों का वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई विरोध करते हैं। द्वीपों और पानी पर दावे और प्रति-दावे अनसुलझे हैं; और दक्षिण चीन सागर लगातार झड़पों के साथ जीवित रहता है। दावेदार देशों ने अपने तरीके से चीनी दावों को पीछे धकेल दिया है, और अपने स्वयं के क्षेत्रीय अधिकारों पर जोर दिया है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नई साझेदारियां उभर रही हैं, चाहे वह क्वाड, एयूकेयूएस या आईपीईएफ हो - इस क्षेत्र के देशों के लिए विकल्प ला रही है।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के द इंडियन फ्यूचर्स एंड फैकल्टी के संस्थापक डॉ. मनीष दाभाडे ने अपने परिचयात्मक संबोधन में दक्षिण चीन सागर में चल रही बहुपक्षीय रणनीतिक प्रतिस्पर्धा की ओर इशारा किया, जिसके तेज होने की संभावना है। अमेरिका और उसके सहयोगी उभरते चीन के साथ 'थ्यूसीडाइड्स ट्रैप' में फंसे हुए हैं। भारत के लिए दक्षिण चीन सागर राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहद सामरिक महत्व रखता है। यह क्षेत्र भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बड़े दायरे में आता है।

पहले सत्र की अध्यक्षता इंस्टीट्यूट ऑफ चाइनीज स्टडीज के मानद अध्येता और विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के डिस्टिनेटर अध्येता राजदूत अशोक कंठ ने की। वक्ताओं में लेफ्टिनेंट जनरल विनोद खंडारे, सलाहकार, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और श्री जयदेव रानाडे, अध्यक्ष, सेंटर फॉर चाइना एनालिसिस एंड स्ट्रैटेजी (सीसीएएस) थे। सत्र में दक्षिण चीन सागर में चीन की मुद्राओं पर चर्चा हुई। समय के साथ, यह क्षेत्र महान शक्ति रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के आधार के रूप में उभरा है। विवाद ने चीन और अमेरिका के बीच पूरे क्षेत्र में राजनीतिक और सैन्य प्रतिद्वंद्विता को तेज कर दिया है और चल रही अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता में घर्षण का एक प्रमुख बिंदु बन गया है। सत्र में चीन के तेजी से सैन्य आधुनिकीकरण का उल्लेख किया गया जिसमें उसके नौसैनिक बेड़े और हिंद-प्रशांत में अपने पदचिह्न का विस्तार करने के उसके प्रयास शामिल हैं।

दूसरे सत्र की अध्यक्षता जर्मनी, इंडोनेशिया, आसियान, इथियोपिया और अफ्रीकी संघ में भारत के पूर्व राजदूत गुरजीत सिंह ने की। वक्ताओं में वियतनाम समाजवादी गणराज्य के दूतावास के मिनिस्टर काउंसलर और डिप्टी चीफ ऑफ मिशन डॉ. दो थान हाई, मेलबर्न विश्वविद्यालय के ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंस्टीट्यूट की सीईओ माननीय लीजा सिंह और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के डीन प्रोफेसर श्रीकांत कोंडापल्ली शामिल थे। इस सत्र में क्षेत्रीय दृष्टिकोण से इस मुद्दे पर चर्चा की गई। दक्षिण चीन सागर के अलग-अलग देशों के लिए अलग-अलग अर्थ और दृष्टिकोण हैं। दावेदार देशों में, वियतनाम दक्षिण चीन सागर में चीनी व्यवहार और रणनीति में बदलाव का निरीक्षण करने वाले पहले देशों में से एक था। यह नोट किया गया कि, चीन के लिए, दक्षिण चीन सागर का नियंत्रण अपनी समृद्धि बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। यह भी कहा गया कि दक्षिण चीन सागर जैसी क्षेत्रीय चुनौतियों से निपटने में बड़े बहुपक्षीय निकायों की अप्रभावीता के कारण मुद्दे-आधारित लघुपक्षवाद का सहारा बढ़ रहा है।

डॉ. संकल्प गुर्जर, अध्येता, भारतीय वैश्विक परिषद, द्वारा लिखित "उत्तर पश्चिम हिंद महासागर की भू-राजनीति: पश्चिम एशियाई राष्ट्रों की रणनीतिक उपस्थिति की खोज" पर सप्रू हाउस पेपर (एसएचपी) चर्चा, 23 सितंबर 2022

भारतीय वैश्विक परिषद के अध्येता डॉ. संकल्प गुर्जर द्वारा 'उत्तर पश्चिम हिंद महासागर की भू-राजनीति: पश्चिम एशियाई राष्ट्रों की रणनीतिक उपस्थिति की खोज' विषय पर 23 सितंबर 2022 को सप्रू हाउस पेपर प्रस्तुति का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता राजदूत (सेवानिवृत्त) अनिल त्रिगुणायत ने की। आमंत्रित चर्चाकारों में डॉ. अल्विते सिंह निंगथोउजम, सहायक प्रोफेसर, सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, पुणे; और, प्रोफेसर अपराजिता बिस्वास, पूर्व प्रोफेसर और सेंटर फॉर अफ्रीकन स्टडीज, मुंबई विश्वविद्यालय के निदेशक थे। यह शोध-पत्र उत्तर पश्चिम हिंद महासागर में छह पश्चिम एशियाई देशों अर्थात कतर, तुर्की, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इजरायल की बढ़ती व्यस्तताओं पर केंद्रित है और इस जुड़ाव के प्रमुख चालकों की पड़ताल करता है।

भारतीय वैश्विक परिषद के अध्येता डॉ. टेशू सिंह द्वारा लिखित "चीन और हिंद-प्रशांत: मुद्दे और चिंताएं" पर सप्रू हाउस पेपर (एसएचपी) चर्चा, 29 सितंबर 2022

भारतीय वैश्विक परिषद ने 29 सितंबर 2022 को भारतीय वैश्विक परिषद के अध्येता डॉ. टेशू सिंह द्वारा 'चीन और हिंद-प्रशांत: मुद्दे और चिंताएं' पर सप्रू हाउस पेपर चर्चा का आयोजन किया। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के डीन प्रोफेसर श्रीकांत कोंडापल्ली ने की। आमंत्रित चर्चाकारी थे: कमोडोर गोपाल सूरी, वरिष्ठ अध्येता, समकालीन चीनी अध्ययन केंद्र, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली; और डॉ. प्रशांत कुमार सिंह, एसोसिएट अध्येता, मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान। शोध-पत्र हिंद-प्रशांत क्षेत्र की अवधारणा पर चीनी स्थिति और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उभरते संरचना पर चीन की प्रतिक्रियाओं की जांच करता है।

डॉ. अरशद, अध्येता, भारतीय वैश्विक परिषद, द्वारा लिखित "तुर्की-मिस्र संबंधों के दस वर्ष: टकराव से सुलह" पर सप्रू हाउस पेपर (एसएचपी) चर्चा, 29 सितंबर 2022

भारतीय वैश्विक परिषद ने 29 सितंबर 2022 को भारतीय वैश्विक परिषद के अध्येता डॉ. अरशद द्वारा 'तुर्की-मिस्र संबंधों के दस वर्ष: सुलह के लिए टकराव' पर सप्रू हाउस पेपर चर्चा का आयोजन किया। इसकी अध्यक्षता राजदूत राहुल कुलश्रेष्ठ, प्रोफेसर, मिस्र और तुर्की के पूर्व राजदूत ने की। तुर्की के यिलदिरिम बेयाजित विश्वविद्यालय के डॉ. ओमैर अनस ने भाग लिया। शोध-पत्र पिछले एक दशक में तुर्की और मिस्र के बीच संबंधों की बदलती गतिशीलता को ट्रैक और विश्लेषण करता है।

हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (आईओआरए) के महासचिव महामहिम सलमान अल फरीसी द्वारा "आईओआरए के 25 वर्ष: एक समृद्ध, सतत और शांतिपूर्ण हिंद महासागर क्षेत्र की दिशा में काम करना" पर 39 वां सप्रू हाउस व्याख्यान, 30 सितंबर 2022

हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (आईओआरए) के महासचिव महामहिम सलमान अल फरीसी ने 30 सितंबर 2022 को "आईओआरए के 25 वर्ष: एक समृद्ध, सतत और शांतिपूर्ण हिंद महासागर क्षेत्र की ओर काम करना" विषय पर 39 वां सप्रू हाउस व्याख्यान दिया। सप्रू हाउस व्याख्यान की अध्यक्षता भारतीय वैश्विक परिषद की महानिदेशक राजदूत विजय ठाकुर सिंह ने की। भारत में इंडोनेशिया गणराज्य की राजदूत महामहिम इना एच. कृष्णमूर्ति और विदेश मंत्रालय के भारत-प्रशांत प्रभाग की संयुक्त सचिव सुश्री गीतिका श्रीवास्तव ने विशेष टिप्पणी की। व्याख्यान का आयोजन नई दिल्ली में इंडोनेशियाई दूतावास के सहयोग से किया गया था।

आईओआरए के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारतीय वैश्विक परिषद के महानिदेशक ने आईओआरए के संस्थापक सदस्य और आईओआरए की यात्रा में प्रमुख समर्थक के रूप में भारत की भूमिका को याद किया। वर्ष 2011-13 के दौरान भारत की अध्यक्षता में समुद्री सुरक्षा, व्यापार और निवेश, आपदा जोखिम प्रबंधन, मत्स्य पालन प्रबंधन, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान तथा शिक्षाविदों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के छह प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर प्रकाश डाला गया। दो फोकस क्षेत्रों, समुद्री अर्थव्यवस्था और महिला सशक्तिकरण को बाद में जोड़ा गया। उन्होंने कहा कि आईओआरए का एक व्यापक एजेंडा है, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों की वृद्धि और विकास में योगदान करना है। भारत हिंद महासागर क्षेत्र और व्यापक हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख हितधारक है। आईओआर के साथ भारत का जुड़ाव गहरा है। उन्होंने मॉरीशस में 2015 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित सागर विजन और 2019 में भारत-प्रशांत समुद्री पहल को याद किया। उन्होंने कहा कि आईपीओआई के सात स्तंभ आईओआरए के फोकस क्षेत्रों के पूरक हैं। उन्होंने आईओआरए के साथ भारतीय वैश्विक परिषद के सहयोग और हिंद महासागर संवाद के दो संस्करणों - आईओआरए की ट्रैक 1.5 पहल - जिनकी इसने 2019 और 2021 में मेजबानी की थी, भारतीय वैश्विक परिषद द्वारा 2021 में आईओआरए सदस्य राष्ट्रों के लिए आयोजित यूएनसीएलओएस पर क्षमता निर्माण कार्यशाला और 2019-21 में भारतीय वैश्विक परिषद/भारत द्वारा धारित आईओआरए अकादमिक समूह की अध्यक्षता।

भारत में इंडोनेशिया के राजदूत ने कहा कि आईओआरए एक स्थिर और समृद्ध हिंद-प्रशांत के लिए चर्चा का मंच हो सकता है। आईओआरए को बदलते समय के अनुरूप सामंजस्य बैठाना होगा। आईओआरए हिंद महासागर क्षेत्र को सतत वैश्विक विकास के नए केंद्र के रूप में बढ़ावा दे सकता है। उन्होंने उल्लेख किया कि वर्तमान आईओआरए अध्यक्ष बांग्लादेश ने ढाका विकास पहल (डीडीआई) शुरू की है जो आईओआरए के मौजूदा तंत्र का पूरक हो सकता है। सुश्री गीतिका श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव, भारत-प्रशांत, विदेश मंत्रालय, भारत ने जोर देकर कहा कि 23 सदस्यों और 10 संवाद भागीदारों के साथ, आईओआरए आईओआर में सबसे बड़ा और पूर्व-प्रतिष्ठित संगठन है। भारत आपदा राहत प्रयासों और अकादमिक और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संपर्कों जैसे क्षेत्रों में आईओआरए के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रहा है। भारत आईओआरए फंड में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है। आईओआरए का संस्थापक सदस्य होने के नाते भारत इसे सुदृढ़ बनाने

के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। आईओआरए हिंद-प्रशांत के प्रति अपने दृष्टिकोण सहित क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के सभी समकालीन मुद्दों के साथ सही ढंग से जुड़ रहा है।

आईओआरए के महासचिव महामहिम सलमान अल फरीसी ने पिछले 25 वर्षों में आईओआरए की प्रमुख उपलब्धियों और फोकस क्षेत्रों पर प्रकाश डाला। उन्होंने आईओआरए के उद्देश्यों, कार्यकरण और प्रभाव के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि हिंद महासागर दुनिया के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। यह 36 अर्थव्यवस्थाओं और पांच उप-क्षेत्रों का आवास है। यह वैश्विक व्यापार और निवेश का केंद्र भी है। आईओआर तेल और गैस जैसे प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। वैश्विक मछली उत्पादन का पांचवां हिस्सा हिंद महासागर में होता है। 1997 में आईओआरए का गठन न केवल सरकार द्वारा संचालित प्रक्रिया थी, बल्कि अकादमिक और व्यवसाय द्वारा समर्थित थी। आईओआरए चार्टर सर्वसम्मति-आधारित और गैर-दखल देने वाले दृष्टिकोण के माध्यम से समझ और पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग का विस्तार करना चाहता है। आईओआरए की सफलता क्षेत्र को एक साथ रखने और संलग्न रखने में है। द्विपक्षीय मुद्दे और तनाव विभाजनकारी कारक नहीं रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में आईओआरए की सदस्यता और संवाद भागीदारों की संख्या बढ़ी है। अन्य प्रासंगिक संगठनों के साथ आईओआरए के सहयोग का विस्तार और सुदृढ़ीकरण करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि 25वीं वर्षगांठ संगठन का कद बढ़ाने का अवसर है। अकादमिक समुदाय को अधिक व्यस्त होने और आईओआरए की सफलताओं और चुनौतियों के बारे में लिखने की आवश्यकता है। वर्तमान में, आईओआरए एक चुनौतीपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में काम कर रहा है। आईओआरए आईओआरए का हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण विकसित करने की प्रक्रिया में है। कोविड-19 के मद्देनजर जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य चुनौतियां अन्य दो महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। आईओआरए को आईओआर में पूर्व-प्रतिष्ठित संगठन के रूप में सेवा करने के लिए अधिक उच्च-स्तरीय राजनीतिक समर्थन की आवश्यकता है। आईओआरए को सचिवालय को सुदृढ़ करने और अधिक जन-केंद्रित और ठोस विकास परियोजनाओं के लिए अधिक वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है। उन्होंने इस संदर्भ में बांग्लादेश की ढाका विकास पहल के वर्तमान अध्यक्ष का उल्लेख किया।

आउटरीच कार्यक्रम

"नया अफगानिस्तान: चुनौतियां और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया" शीर्षक से दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग, दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय, 9-10 सितंबर 2022

अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग, दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय ने 9-10 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में भारतीय वैश्विक परिषद (आईसीडब्ल्यूए) के सहयोग से "नया अफगानिस्तान: चुनौतियां और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया" नामक दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। भारतीय वैश्विक परिषद् की अध्येता डॉ. अन्वेषा घोष ने इस कार्यक्रम में परिषद का प्रतिनिधित्व किया। सम्मेलन में उद्घाटन और समापन सत्र सहित पांच सत्र थे। सम्मेलन हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया गया था। एसएयू के कार्यवाहक अध्यक्ष प्रोफेसर आरके मोहंती ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता एसएयू में सामाजिक विज्ञान संकाय के डीन प्रोफेसर संजय चतुर्वेदी ने की। भारतीय वैश्विक परिषद् प्रतिनिधि को उद्घाटन सत्र में अपनी टिप्पणी देने के लिए भी आमंत्रित किया गया था। उद्घाटन सत्र के बाद प्रोफेसर सी राजा मोहन ने मुख्य भाषण दिया। सत्र I और सत्र II के विषय "अंतर्राष्ट्रीय चिंता और प्रतिक्रियाएं" और "क्षेत्रीय प्रतिक्रियाएं" थे। तीसरा सत्र तालिबान की वापसी पर केंद्रित था। सम्मेलन का समापन भाषण राजदूत टी. सी. ए. राघवन ने दिया।

भारतीय वैश्विक परिषद प्रकाशन

क्षेत्र अध्ययन पर सप्रू हाउस साउंडिंग

दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में चीन का बीआरआई: सहयोग, विरोधाभास और चिंताएं

संजीव कुमार द्वारा संपादित

(भारतीय वैश्विक परिषद; के.वी. पब्लिशर्स, 2022)

प्रस्तावना

भारत और चीन दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। उभरती वैश्विक व्यवस्था में दोनों का रणनीतिक और आर्थिक भार है। भारत की विदेश नीति और चीन की नीतियों और दृष्टिकोणों के क्षेत्र में विकास को रणनीतिक समुदाय द्वारा विश्व स्तर पर बहुत रुचि के साथ देखा जाता है, जो हमेशा शिक्षाविदों और विद्वानों के हित को आकर्षित करता है।

भारतीय वैश्विक परिषद् चीन के घटनाक्रम पर नजर रखे हुए है। परिषद चीन के विभिन्न आयामों पर सम्मेलन, सेमिनार, संवाद, व्याख्यान और आउटरीच कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसमें इसकी आंतरिक और बाहरी गतिशीलता भी शामिल है।

परिषद में चीन के विभिन्न आयामों के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करने वाले कई प्रकाशन हैं, जिनमें शामिल हैं: चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 18 वीं राष्ट्रीय कांग्रेस: चीन के लिए एक प्रमुख ट्यूरिंग प्वाइंट; भारत-चीन सीमा मुद्दे: निपटान के लिए खोज; चीन: छाया में कन्फ्यूशियस; एक चीन प्राइमर: एक संस्कृति और एक पड़ोसी का परिचय और; चीन और यूरेशियन क्षेत्र: भौगोलिक और भू-राजनीतिक प्रभाव।

वर्तमान अध्ययन का मुख्य उद्देश्य बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) को अलग-अलग देशों के साथ-साथ दुनिया भर के क्षेत्रों के दृष्टिकोण से जांचना है। विशेष रूप से हमारे पड़ोस में बीआरआई के निहितार्थ, रुचि और जांच का विषय है। संपादित वॉल्यूम विभिन्न क्षेत्रों से कई व्यापक रुझानों की पहचान करता है और हाइलाइट करता है; और बीआरआई का विश्लेषण करने और भाग लेने वाले देशों में उभरती धारणाओं और चिंताओं को समझने के संदर्भ में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

बीआरआई पर भारत का रुख स्पष्ट और सुसंगत है। कनेक्टिविटी पहल सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों पर आधारित होनी चाहिए। उन्हें राष्ट्रों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए और खुलेपन, पारदर्शिता और वित्तीय जिम्मेदारी के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए।

क्षेत्र अध्ययन में विशेषज्ञता रखने वाले भारतीय वैश्विक परिषद् विद्वानों ने मूल्यवान योगदान और अंतर्दृष्टि दी है, विशेष रूप से, डॉ. संजीव कुमार, वरिष्ठ अध्येता, जिन्होंने इस खण्ड का संपादन किया है। मुझे विश्वास है कि यह छात्रवृत्ति और सभी तिमाहियों में इस विषय पर बहस को और समृद्ध करेगा।

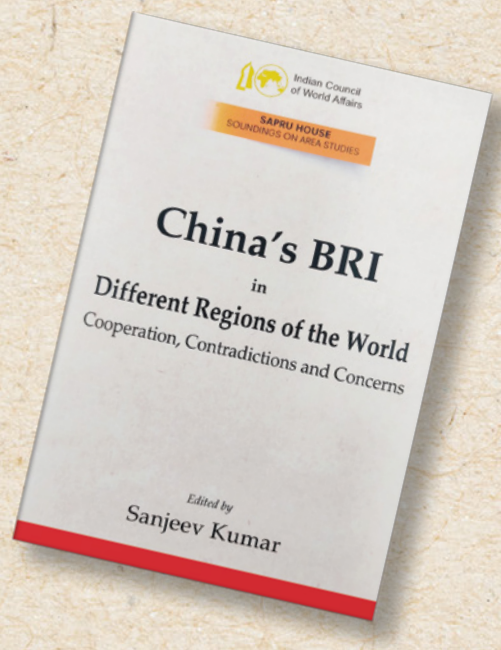

राजदूत विजय ठाकुर सिंह

महानिदेशक, भारतीय वैश्विक परिषद

7 जुलाई 2022

भारतीय वैश्विक परिषद प्रकाशन

मुद्दा संक्षिप्त

1. डॉ. तेमजेनमेरेन आओ, मार्कोस जूनियर के नेतृत्व में एक नए प्रशासन के तहत फिलीपींस (05 जुलाई 2022)
2. डॉ. अंकिता दत्ता, नाटो के मैड्रिड शिखर सम्मेलन का विश्लेषण (07 जुलाई 2022)
3. डॉ. स्तुति बनर्जी, राष्ट्रपति बाइडेन का मध्य पूर्व असमंजस (07 जुलाई 2022)
4. डॉ. समथा मल्लेम्पति, श्रीलंका में घटनाक्रम : धूमिल होता आर्थिक और राजनीतिक भविष्य? (19 जुलाई 2022)
5. डॉ. अथर ज़फर, सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए ताजिकिस्तान ने साझेदारों के साथ सहयोग मजबूत किया (26 जुलाई 2022)
6. डेल्मा जोसेफ, अब्राहम समझौते का अतीत, वर्तमान और भविष्य (02 अगस्त 2022)
7. डॉ. हिमानी पंत, यूक्रेन में वर्तमान स्थिति और रूसी विदेश नीति पर इसका प्रभाव (04 अगस्त 2022)
8. कौशिक नाग, क्या अफ्रीका यूरोप के लिए रूसी गैस निर्यात के लिए एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में उभर सकता है? (10 अगस्त 2022)
9. डॉ. फज़ुर रहमान सिद्दीकी, राष्ट्रपति बाइडन का पश्चिम एशिया दौरा: राजनीतिक यथार्थवाद का प्रतिबिंब (12 अगस्त 2022)
10. ईशानी अग्निहोत्री, आई2यू2: पहलू और संभावनाएं (16 अगस्त 2022)
11. डॉ. अन्वेषा घोष, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के एक वर्ष बाद (17 अगस्त 2022)
12. आश्रीती गौतम, नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन की राजनीति (22 अगस्त 2022)
13. डॉ. टेशू सिंह, ताइवान जलडमरूमध्य में मार्ग में तीव्र कटार: हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए निहितार्थ (22 अगस्त 2022)
14. डॉ. सुदीप कुमार, शिंजो आबे की विरासत और भारत-जापान संबंध (05 सितंबर 2022)
15. डॉ. संजीव कुमार, चीन की वैश्विक विकास पहल का एक वर्ष: बयानबाज़ी में अधिक, वास्तविकता में कम? (14 सितंबर 2022)
16. जयवीर सिंह, ब्रिक्स के नेतृत्व में वित्तीय विविधीकरण की संभावना (21 सितंबर 2022)
17. डॉ. अथर ज़फर, एससीओ समरकंद शिखर सम्मेलन और भारत की अध्यक्षता: एक परिप्रेक्ष्य (23 सितंबर 2022)

दृष्टिकोण

1. डॉ. प्रज्ञा पांडे, रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग: भारत-ऑस्ट्रेलिया साझेदारी के प्रमुख स्तंभ (13 जुलाई 2022)
2. डॉ. अन्वेषा घोष, अफगानिस्तान में भीषण भूकंप के बाद भारत की पहल (13 जुलाई 2022)
3. डॉ. लक्ष्मी प्रिया, पश्चिम एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका (डब्ल्यूएएनए) क्षेत्र में रियाद द्वारा 'संतुलन का प्रयास' (14 जुलाई 2022)
4. डॉ. संकल्प गुर्जर, सामरिक सीमा का विस्तार: इंडो-पैसिफिक, अफ्रीका और शिंजो आबे (14 जुलाई 2022)

5. डॉ. प्रज्ञा पांडे, प्रशांत द्वीप समूह मंच (पीआईएफ) से किरिबाती के हटने की वजह से उपजा प्रशांत में क्षेत्रवाद संकट (20 जुलाई 2022)
6. डॉ. स्तुति बनर्जी, लैंडलॉक एससीओ राष्ट्रों के लिए ईरान के चाबहार बंदरगाह का बढ़ता महत्व (20 जुलाई 2022)
7. डॉ. फज़ज़ुर रहमान सिद्दीकी, ट्यूनीशिया में संवैधानिक जनमत संग्रह: एक सिंहावलोकन (12 अगस्त 2022)
8. डॉ. संकल्प गुर्जर, शक्ति राजनीति के बीच अफ्रीका के लिए नई अमेरिकी रणनीति (12 अगस्त 2022)
9. डॉ. अथर जफर, लैंडलॉक एससीओ राष्ट्रों के लिए ईरान के चाबहार बंदरगाह का बढ़ता महत्व (12 अगस्त 2022)
10. डॉ.पुनीत गौर, मध्य एशिया में चौथी सलाहकार बैठक पर एक परिप्रेक्ष्य (09 सितंबर 2022)
11. डॉ. लक्ष्मी प्रिया, ब्रिक्स की सदस्यता पर डब्ल्यूएएनए देशों की नजर (13 सितंबर 2022)
12. डॉ. श्रीपति नारायणन, दक्षिणपूर्व एशिया के साथ भारत की सैन्य कूटनैतिक भागीदारी (14 सितंबर 2022)
13. डॉ. अर्शद, सुरक्षा और विकास पर जेद्दा शिखर सम्मेलन: पहलू और संभावनाएं (14 सितंबर 2022)
14. डॉ. तेमजेनमेरेन आओ, आसियान और भारत-प्रशांत आर्थिक ढांचा (23 सितंबर 2022)
15. डॉ. लक्ष्मी प्रिया, खाड़ी देश और एससीओ का विस्तार (28 सितंबर 2022)
16. डॉ. संकल्प गुर्जर, इथियोपिया में संघर्ष और हॉर्न ऑफ़ अफ्रीका में क्षेत्रीय (अ)सुरक्षा (28 सितंबर 2022)

सप्रू हाउस पेपर

1. डॉ. तेमजेनमेरेन आओ, दक्षिण पूर्व एशिया में लोकतंत्र: उभरते रुझान और संक्रमण को आकार देने वाले कारक

अतिथि कॉलम

1. राजदूत डीपी श्रीवास्तव, भारत-ईरान संबंध: एक पूर्व राजदूत लिखते हैं (18 अगस्त 2022)
2. राजदूत डीबी वेंकटेश वर्मा, प्रोफेसर के वारिकू और प्रोफेसर एसके पांडे, शंघाई स्पिरिट का नवीनीकरण: शंघाई सहयोग संगठन की भारत की अध्यक्षता (6 सितंबर 2022)
3. श्री वी श्रीनिवास, G20@2023: भारतीय अध्यक्षता का रोडमैप (9 सितंबर 2022)
4. प्रोफेसर चिंतामणि महापात्र, विस्तारित परमाणु निवारण पर पुनर्विचार: प्रासंगिकता और चुनौतियां (15 सितंबर 2022)
5. राजदूत राहुल कुलश्रेष्ठ, तुर्की की क्वेस्ट फॉर स्टेटस: पॉलिटिक्स ऑफ एलायंस एंड काउंटर एलायंस - एक पूर्व राजदूत लिखते हैं (26 सितंबर 2022)

पुस्तकें

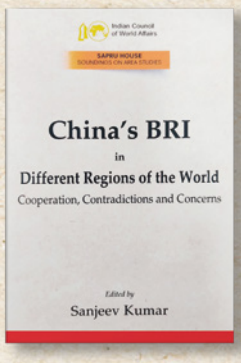

China's BRI in Different Regions of the World: Cooperation, Contradictions and Concerns

By Sanjeev Kumar,

(Indian Council of World Affairs; KW Publishers, 2022)

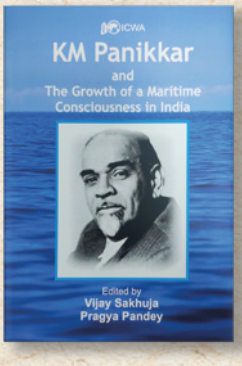

K M Panikkar and The Growth of a Maritime Consciousness in India,

By Vijay Sakhuja & Pragya Pandey,

(Indian Council of World Affairs; Vij Books, 2022)

Legitimacy of Power: The Permanence of Five in the Security Council
(Malayalam Edition)

By Dilip Sinha,

(ICWA;
Prabhat Prakashan, 2022)

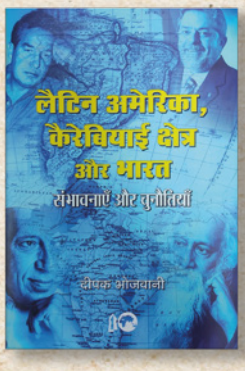

लैटिन अमेरिका, कैरेबियाई क्षेत्र और भारत : संभावनायँ और चुनौतियाँ

Hindi Edition by
दीपक भोजवानी (भारतीय वैश्विक परिषद, प्रभात प्रकाशन, 2022)

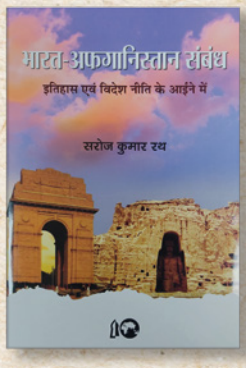

भारत- अफगानिस्तान संबंध: इतिहास एवं विदेश नीति के आईने में

सरोज कुमार रथ (भारतीय वैश्विक परिषद, प्रभात प्रकाशन, 2022)

विशेष प्रकाशन

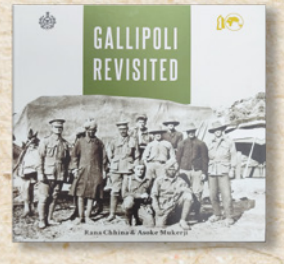

Gallipoli Revisited

By Rana Chhina & Asoke Mukerji,

(ICWA - USI, 2022)

(15 July 2022)

Renewing the Shanghai Spirit: India's Presidency of Shanghai Cooperation Organisation

Edited By Amb. D.B. Venkatesh Varma, Prof. K. Warikoo & Prof. S.K. Pandey

(6 September 2022)

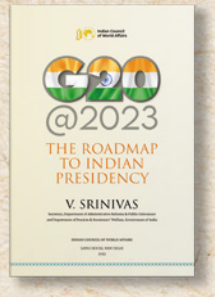

G20@2023: The Roadmap to Indian Presidency

Edited By Sh. V. Srinivas

(9 September 2022)

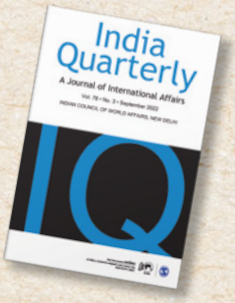

इण्डिया क्वार्टरली
वैश्विक विचार एवं व्यव्हार शोध पत्रिका
खंड 78, अंक 3, जुलाई-सितंबर 2022

संपादकीय

जैसे-जैसे दुनिया एक 'अभूतपूर्व' घटना से दूसरी 'अभूतपूर्व' घटना में गुजरती है, ऐसा लगता है कि शब्द ने अपना अर्थ खो दिया है। अगर हम सोचते हैं कि कोविड-19 अभूतपूर्व था, तो अब लगभग पीछे की ओर, ऐसा प्रतीत होता है कि अभूतपूर्व केवल इक्कीसवीं सदी की प्रौद्योगिकियों को दुनिया भर में वास्तविक समय में रिकॉर्ड करने और रिपोर्ट करने में सक्षम होने के तरीके से संबंधित है। व्यक्तिगत राष्ट्रों, वैश्विक संस्थानों और बड़े निगमों की प्रतिक्रिया उनकी स्थापित प्रथाओं से अलग नहीं हुई। इसलिए यूक्रेन युद्ध के साथ, जहां यूरोप के इतिहास में लिखे गए रणनीतिक हितों के साथ रेखाएं खींची जाती हैं। इसलिए, यूरोपीय और अमेरिकी हथियारों की अंतहीन आपूर्ति युद्ध को बनाए रखती है, इसकी समाप्ति नहीं, यहां तक कि रिपोर्ताज कहानी बन जाती है।

फिर भी 'अभूतपूर्व' शब्द का अर्थ इतना नहीं है कि यह क्या दर्शाता है, लेकिन अभूतपूर्व की भावना कैसे विशालता की भावना के नुकसान को संभव बनाती है, जिससे अनिवार्य रूप से हिंसा के अधिक स्तर की सामाजिक स्वीकृति होती है। बीसवीं शताब्दी की हिंसा के बारे में लिखते हुए, दिवंगत सांस्कृतिक आलोचक जॉर्ज स्टेनर ने हमारी अपनी दुर्दशा के साथ एक सादृश्य में बताया: पेचीदा सुझाव है कि प्रलय की आसानी 1920 के दशक में मुद्रा के पतन से संबंधित है। बड़ी संख्या ने एक अस्पष्ट भयावह, अवास्तविक अर्थ को छोड़कर सभी को खो दिया। एक लाख, फिर एक मिलियन, फिर रोटी खरीदने या बस टिकट के लिए भुगतान करने के लिए एक अरब के निशान को देखने के बाद, आम आदमी ने ठोस विशालता की सभी धारणा खो दी। वही बड़ी संख्या अवास्तविकता के साथ दागदार लोगों के गायब होने और परिसमापन है। (जॉर्ज स्टेनर, 1997, पृष्ठ51)।

अतः, उन्होंने नोट किया: हमारी वर्तमान स्थिति के बारे में कुछ भी स्वाभाविक नहीं है। हमारे वर्तमान ज्ञान निर्देशक जनरल में कोई आत्म-स्पष्ट तर्क या गरिमा नहीं है कि 'कुछ भी संभव है'। वास्तव में, इस तरह के जानकार महानिदेशक भ्रष्ट करते हैं और आक्रोश की दहलीज को कम करते हैं .... आतंक के साथ हमारे परिचित की सुन्न विलक्षणता एक कट्टरपंथी मानव यी हार है। (स्टीनर, 1997, पृष्ठ 48-49) आक्रोश की हानि की परिपत्रता, यह महसूस करना कि कुछ भी संभव है, और हिंसा की स्वीकृति आज दुनिया को चिह्नित करती है। इसलिए, विश्व स्तर पर कोविड-19 के कारण मरने वालों की संख्या पर डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट आक्रोश पैदा करती है क्योंकि बहुत कम लोगों की गिनती की गई थी, बल्कि बहुत सारे थे। यूक्रेनी शरणार्थियों के लिए करुणा रूसी विश्वासघात पर एक आक्रोश द्वारा चिह्नित है, लेकिन अपमानजनक तथ्य से अलग है कि दुनिया भर में 79.5 मिलियन लोग आज शरणार्थी हैं। इसे संदर्भ में रखने के लिए, 79.5 मिलियन कनाडा (38,246,108) और ऑस्ट्रेलिया (25,684,000) की आबादी से बड़ा है। चीन द्वारा अपने उइगर अल्पसंख्यक को कैद करने पर चर्चा, जैसा कि यह है, अमेरिकी और कनाडाई धार्मिक शैक्षिक प्रतिष्ठानों में बड़ी संख्या में अमेरिकी भारतीय बच्चों की हालिया हत्याओं की अनदेखी करता है और इसलिए, विकसित और कम विकसित समाजों में सीमांत समूहों के लिए मानवाधिकारों का बड़ा प्रश्न है।

जैसे-जैसे यह सदी अपने दूसरे दशक में आगे बढ़ती है, चीन और रूस जैसे राज्य अपने इतिहास के राष्ट्रवादी पठन द्वारा निर्धारित भू-राजनीतिक पहुंच हासिल करने के लिए भूमि और पानी पर बड़ी, अधिक आधुनिक और खतरनाक सेनाओं को फेरबदल करते हैं। अस्थिर भू-राजनीतिक प्रगति को दक्षिण एशिया में आर्थिक आउटरीच के रूप में लपेटा जाता है, राजनीतिक स्थिरता को कमजोर करता है और घरेलू हिंसा को उजागर करता है, और आगे, नवजात गठबंधन एक संकटग्रस्त पश्चिम के मूल्यों पर प्रश्न उठाते हैं जो अपनी लड़ाई के विरुद्ध दबाव डालता है। अधिक हिंसा की संभावना, न केवल असंतोष, हमें परेशान करना शुरू कर देती है। ये झूठे भय नहीं हैं, जैसा कि इंडिया क्वार्टरली नोट के इस अंक में निबंध उठाते हैं, जैसा कि उन्हें करना चाहिए, सुन्नता की परिपत्रता और हिंसा की बढ़ती सीमा की स्वीकृति के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाने चाहिए।

संदर्भ स्टेनर, जी (1971)। [एसपी 7] ब्लूबियर्ड के कैसल में: संस्कृति की पुनर्परिभाषा की दिशा में कुछ नोट्स (टीएस एलियट मेमोरियल व्याख्यान)। येल यूनिवर्सिटी प्रेस।

मधु भल्ला
संपादक, इंडिया क्वार्टरली, भारतीय वैश्विक परिषद

भारतीय वैश्विक परिषद् के बारे में

भारतीय वैश्विक परिषद (ICWA) की स्थापना 1943 में सर तेज बहादुर सप्रू और डॉ एच.एन. कुंजरू के नेतृत्व में प्रख्यात बुद्धिजीवियों के एक समूह द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर एक भारतीय परिप्रेक्ष्य बनाना और विदेश नीति के मुद्दों पर ज्ञान और सोच के भंडार के रूप में कार्य करना था। परिषद आज एक आंतरिक संकाय के साथ-साथ बाहरी विशेषज्ञों के माध्यम से नीति शोध करती है। यह सम्मेलनों, संगोष्ठियों, गोलमेज परिचर्चाओं, व्याख्यानों सहित बौद्धिक गतिविधियों की एक श्रृंखला नियमित रूप से आयोजित करती है और कई प्रकाशनों का प्रकाशन करती है। इसमें एक बहुत सी पुस्तकों से सुसज्जित पुस्तकालय, एक सक्रिय वेबसाइट है, और यह 'इंडिया क्वार्टरली' पत्रिका प्रकाशित करती है। अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर बेहतर समझ को बढ़ावा देने और आपसी सहयोग के क्षेत्रों को विकसित करने के लिए आईसीडब्ल्यूए ने अंतरराष्ट्रीय थिंक टैंकों और अनुसंधान संस्थानों के साथ 50 से अधिक समझौता ज्ञापन किए हैं। परिषद् की भारत में अग्रणी शोध संस्थानों, थिंक टैंकों और विश्वविद्यालयों के साथ भी साझेदारी है।

मेंटर : राजदूत विजय ठाकुर सिंह, महानिदेशक, आईसीडब्ल्यूए, सप्रू हाउस, नई दिल्ली

संपादक : श्रीमती नूतन कपूर महावर, संयुक्त सचिव, आईसीडब्ल्यूए, सप्रू हाउस, नई दिल्ली

प्रबंध संपादक : डॉ. निवेदिता रे, निदेशक अनुसंधान, आईसीडब्ल्यूए

सहायक संपादक : डॉ. ध्रुबज्योति भट्टाचार्जी, अनुसंधान अध्येता, आईसीडब्ल्यूए

सहायक : श्री कौशिक नाग, रिसर्च इंटर्न

हमसे जुड़ें

/Sapru.House @ICWA_NewDelhi /ICWA_NewDelhi www.icwa.in

/company/indian-council-of-world-affairs1

आईसीडब्ल्यूए, सप्रू हाउस, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली - 110001 द्वारा प्रकाशित समाचार पत्रक

वेबसाइट: http://www.icwa.in; दूरभाष नं 011-23317246 फैक्स नंबर 011-23310638